वर्ष : 34 | अंक : 379 | मुंबई, शनिवार, 28 मार्च 2026 | RNI: MAHHIN/49994/91 | मूल्य : 3 रुपए | epaper.dobajedopahar.com | संपादक : अरुण लाल | संरक्षक : एन. के. पुरोहित

DBD दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

नायरा एनर्जी बढ़ा चुकी है दाम

इससे पहले निजी कंपनी नायरा पेट्रोल की कीमत में पांच रुपए और डीजल के दामों में तीन रुपए की वृद्धि कर चुकी है। नायरा के पेट्रोल पंप पर अब पेट्रोल 100 .71 रुपये और डीजल 91 .31 रुपये लीटर है। बाजार के 90 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण रखने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अभी कीमतों को स्थिर रखा है।

कितना पड़ता है असर?

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों का सीधा असर पड़ता है। अमूमन यह माना जाता है कि कच्चा तेल एक डॉलर प्रति बैरल महंगा होता है, तो पेट्रोल व डीजल की लागत 50- 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ जाती है। कच्चा तेल तीस डॉलर के आसपास बढ़ा है, तो पेट्रोल व डीजल की कीमत 15 से 18 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकती है। इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। कंपनियों का कुल दैनिक घाटा लगभग 2,400 करोड़ रुपये है।

फिलहाल दाम बढ़ने की संभावना कम

केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती कर फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का दबाव कम करने की कोशिश की है। पश्चिम एशिया संकट लंबा चलता है और कच्चे तेल की कीमत और बढ़ती है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों उपभोक्ताओं पर इसका भार डाल सकती है। ऊर्जा क्षेत्र के जानकार मानते हैं कि ईरान और अमेरिका व इजरायल युद्ध जारी रहने पर कच्चे तेल की कीमत और बढ़ेंगी।

'लॉकडाउन' की अफवाह पूरी तरह से गलत: पुरी

पुरी ने कहा, सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसे समय में शांत और एकजुट रहना महत्वपूर्ण है। अफवाह फैलाना गैर-जिम्मेदाराना और नुकसानदायक है। दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में कीमतों में लगभग 30 से 50 प्रतिशत, उत्तरी अमेरिकी देशों में 30 प्रतिशत, यूरोप में 20 प्रतिशत और अफ्रीकी देशों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। मंत्री ने कहा कि सरकार के पास दो ही विकल्प थे-या तो कीमतों में भारी बढ़ोतरी की जाए या फिर अपने वित्त पर इस बोझ को खुद सहा जाए।

कटौती तत्काल प्रभाव से लागू

वित्त मंत्रालय की तरफ से 26 मार्च को जारी अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर तीन रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर यह शुल्क पहले के 10 रुपए से घटाकर शून्य कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि शुल्क में यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 1.75 लाख करोड़ रुपये का राजस्व बोझ पड़ने का अनुमान है।

आम जनता को राहत

- पेट्रोल-डीजल के दाम अभी नहीं बढ़ेंगे, एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घटी
- कच्चा तेल महंगा होने से कंपनियों को ₹30 प्रति लीटर तक घाटा हो रहा था
- सरकार सहेगी ₹1.75 लाख करोड़ का बोझ

एजेंसी । नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में दस-दस रुपए की कटौती की है। इस कटौती का आम उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्पाद शुल्क में इस कटौती के बाद पेट्रोल पर प्रभावी उत्पाद शुल्क 11.9 रुपये प्रति लीटर होगा (जिसमें 1.40 रुपये मूल उत्पाद शुल्क, 3 रुपये विशेष अतिरिक्त शुल्क, 2.50 रुपये कृषि उपकर और पांच रुपये सड़क बुनियादी ढांचा उपकर शामिल है)। वहीं, डीजल पर प्रभावी शुल्क 7.80 रुपये प्रति लीटर (1.80 रुपये मूल शुल्क, 4 रुपये कृषि उपकर और 2 रुपये सड़क उपकर) रह जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर शुल्क लगा दिया है। सरकार ने डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन पर 29.5 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया है।पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 70 से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल प्रति पहुंच गई हैं। इससे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 24 और डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर का नुकसान सहना पड़ रहा है। ऐसे में उत्पाद शुल्क कम होने से तेल कंपनियों को कुछ राहत मिलेगी और कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का फिलहाल सीधा असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा।

सरकार के पास दो ऑप्शन थे— या तो पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाकर बोझ कंज्यूमर्स पर डाला जाए, या खुद नुकसान उठाकर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाए। हमने दूसरा ऑप्शन चुना।

- सुजाता शर्मा
पेट्रोलियम मंत्रालय

पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनज़र राज्यों की तैयारियों, आपात योजनाओं और समन्वय तंत्र की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य 'टीम इंडिया' की भावना के तहत केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना रहा, ताकि किसी भी संभावित स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो सके, इसलिए कैबिनेट सचिवालय द्वारा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्य सचिवों के साथ अलग से बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें इन राज्यों की तैयारियों और रणनीतियों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही, केंद्र ने सभी राज्यों को सतर्क रहने और समन्वित कार्रवाई के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए।

कच्चे घर अब होंगे पक्के

धीरज सिंह । मुंबई

राज्य के राजस्व विभाग ने 1 जनवरी 2011 तक के आवासीय अतिक्रमणों को नियमित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस संबंध में शुक्रवार को शासनादेश जारी किया गया। यह नियम मुंबई और मुंबई उपनगर को छोड़कर पूरे राज्य में लागू होगा।

2011 तक के आवासीय अतिक्रमण होंगे नियमित

मुंबई को छोड़ पूरे राज्य में आदेश लागू

500 वर्ग फुट तक मुफ्त, उससे अधिक पर 10% शुल्क

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 500 वर्ग फुट तक के आवासीय अतिक्रमण पूरी तरह मुफ्त नियमित किए जाएंगे। वहीं, इससे अधिक क्षेत्र के लिए बाजार मूल्य का केवल 10 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा।

"राज्य के लाखों गरीब परिवारों को बड़ा दिलासा मिलेगा, उन्हें स्थायी आवास मिलेगा और उनके जीवन में स्थिरता आएगी। सरकार इस योजना की हर तीन महीने में समीक्षा करेगी।

-चंद्रशेखर बावनकुले
राजस्व मंत्री

संयुक्त नाम और अधिकतम सीमा तय

इस योजना के तहत जमीन पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर दी जाएगी और अधिकतम 1500 वर्ग फुट तक ही अतिक्रमण नियमित किए जाएंगे। यदि किसी घर का कुछ हिस्सा व्यवसाय के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो उस पर बाजार मूल्य का 25 प्रतिशत शुल्क देना होगा।

कुछ जमीनों पर अतिक्रमण को नहीं मिलेगी मान्यता

नदी, नाले, सड़क, जंगल, श्मशान, खेल मैदान और स्कूल या अस्पताल के लिए आरक्षित जमीनों पर किए गए अतिक्रमण किसी भी स्थिति में नियमित नहीं किए जाएंगे। ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रमाणपत्र अनिवार्य, विशेष समितियां करेंगी प्रक्रिया पूरी

अतिक्रमण नियमित कराने के लिए 1 जनवरी 2011 से पहले के निवास का प्रमाण जैसे वोटर लिस्ट, बिजली बिल या संपत्ति रसीद देना जरूरी होगा, साथ ही पिछले एक साल का निवास प्रमाण भी अनिवार्य रहेगा। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए जिला, उपविभाग और तहसील स्तर पर विशेष समितियां बनाई गई हैं, जिससे अलग-अलग मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

संदीप गडोली एनकाउंटर केस

मुंबई सेशन कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी

फर्जी एनकाउंटर के आरोप साबित करने में नाकाम रहा अभियोजन पक्ष

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुंबई। मुंबई सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगस्टर संदीप गडोली एनकाउंटर मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें हरियाणा पुलिस के पांच जवान, मॉडल दिव्या पाहुजा की मां सोनिया पाहुजा और वीरेंद्र गुर्जर शामिल थे। अदालत ने कहा कि आरोपियों पर हत्या समेत अन्य धाराओं में लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए।

2016 में हुई थी घटना

यह मामला 7 फरवरी 2016 का है, जब मुंबई के अंधेरी स्थित एक होटल में हरियाणा पुलिस की टीम ने संदीप गडोली को गोली मार दी थी। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि गडोली उस समय निहत्था था और यह एक फर्जी एनकाउंटर था। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर गठित मुंबई पुलिस की एसआईटी ने इस मामले की जांच की थी। जांच में सामने आया था कि यह एक सोची-समझी साजिश थी, जिसमें हरियाणा पुलिस टीम के साथ अन्य लोगों की भी भूमिका थी। मॉडल दिव्या पाहुजा और उनकी मां पर भी

ब्रीफ न्यूज़

सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई महानिदेशक को किया तलब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह नोटिस दि ल्ली में अधिसूचित 173 विरासत स्थलों की संरक्षण स्थिति पर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने के लिए न्यायालय ने एएसआई के महानिदेशक को अगले महीने व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई फरवरी में अदालत द्वारा पारित एक आदेश के बाद की गई है, जिसमें राजधानी में अधिसूचित विरासत स्थलों का प्रबंधन करने वाले कई अधिकारियों से स्थिति रिपोर्ट मांगी गई थी। आईएनटीएसी की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में 1100 से अधिक अधिसूचित धरोहर और संरचनाएं हैं। जबकि 173 स्थल एएसआई के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं।

खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक और पोत सुरक्षित

नई दिल्ली। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे सभी भारतीय नाविक और पोत सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटों में किसी भी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। एक संयुक्त अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में बोलते हुए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय बनाए हुए हैं।उन्होंने कहा, फारसी खाड़ी में, भारतीय झंडे लगे 20 पोत चल रहे हैं, जिन पर लगभग 540 भारतीय सवार हैं। वे भी सुरक्षित हैं।

स्थानीय लोगों की नींद उड़ी, तो बीएमसी ने बदला नियम

मुंबई की म्यूजिकल रोड पर लगा 'नाइट कर्फ्यू'

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

कोस्टल रोड पर बना 'म्यूजिकल रोड' प्रयोग अब विवादों और स्थानीय लोगों की शिकायतों के घेरे में है। मरीन ड्राइव से वर्ली के बीच 'जय हो' की धुन सुनाने वाली इन पट्टियों के शोर से परेशान नागरिकों की राहत के लिए बीएमसी (BMC) ने एक बड़ा और थोड़ा अजीब फैसला लिया है। 11 फरवरी को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अनोखे प्रयोग का उद्घाटन किया था। नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर जाने वाले रास्ते पर सुरंग से बाहर निकलते ही सबसे अंदर वाली लेन में 500 मीटर तक खास 'टेक्सचर्ड' (बनावट वाली) पट्टियां लगाई गई हैं। जब गाड़ी 70 से 80 किमी/घंटा की रफ्तार से इन पर चलती है, तो टायरों के घर्षण से ए.आर. रहमान के मशहूर गाने 'जय हो' की धुन सुनाई देती है।

क्यों शुरू हुआ विवाद?

गाड़ी चलाने वालों के लिए तो यह अनुभव रोमांचक था, लेकिन कोस्टल रोड के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए यह दिन-रात बजने वाला 'शोर' बन गया। लोगों की शिकायत है कि लगातार बजने वाली इस धुन के कारण उनकी शांति भंग हो रही है और रात की नींद में खलल पड़ रहा है। हालांकि ठेकेदार का दावा है कि शोर का स्तर 'सेफ लिमिट' में है, पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा।

बीएमसी का समाधान

स्थानीय लोगों के गुस्से को देखते हुए बीएमसी ने सड़क के उस खास हिस्से (जहाँ पट्टियां हैं) को सप्ताह में तीन दिन कुछ घंटों के लिए बंद करने का फैसला लिया है। शुक्रवार से रविवार तक रात 10 :00 बजे से सुबह 7 :00 बजे के बीच यह धुन नहीं बजेगी। इन घंटों के दौरान वहां बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे।

महिला पुलिसकर्मी ने पिता को मिल्कशेक में दिया जहर

- बेटी सहित चार लोग गिरफ्तार

एजेंसी । नई दिल्ली

महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी जयंत बल्लावर की मौत के तीन साल बाद उनकी हत्या के सिलसिले में उनकी बेटी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उस समय मौत का कारण केवल अचानक हुई बीमारी के रूप में दर्ज किया गया था और किसी भी तरह के अपराध का संदेह नहीं था। 25 अप्रैल, 2023 की सुबह, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी जयंत बल्लावर हमेशा की तरह ड्यूटी के लिए घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उनकी बेटी आर्या, जो खुद एक सेवारत महिला पुलिसकर्मी है, उसने उन्हें एक मिल्कशेक दिया।

तीन साल बाद हुआ हत्या का खुलासा

उस समय, मौत का कारण केवल अचानक हुई बीमारी के रूप में दर्ज किया गया था। किसी भी तरह के अपराध का संदेह नहीं था। फाइल बंद कर दी गई थी। तीन साल बाद, बेटी और तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब इसे एक सोची-समझी हत्या बता रही है।

पाखंडी बाबा का 'अनंत' कांड

- एसआईटी को अब तक मिलीं 50 शिकायतें
- रोजाना आ रहे 15-20 शिकायती कॉल

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुंबई पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दुष्कर्म के आरोपी और स्वयंभू बाबा अशोक खरात के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि अशोक खरात के खिलाफ पांच दिनों में अब तक 50 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। उन्होंने बताया कि टीम को फोन पर रोजाना 15 से 20 शिकायती कॉल आ रहे हैं और इनका सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस ने अब तक अशोक खरात के खिलाफ आठ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की हैं। इन शिकायतों में यौन उत्पीड़न, उगाही और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप शामिल हैं।

खरात के ऑफिस से मिले महत्वपूर्ण दस्तावेज

एसआईटी ने शुक्रवार को फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर नासिक में खरात के कार्यालय का दौरा किया। पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने कार्यालय से कई दस्तावेज, फाइलें, एक डायरी और अन्य कागजात बरामद किए।

हथियार लाइसेंस निलंबित

इस बीच नासिक जिला प्रशासन ने पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी खरात के हथियार लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। प्रशासन का मानना है कि उसके खिलाफ कई मामले दर्ज होने के कारण वह पीड़ितों को धमकाने या डराने के लिए हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। नासिक कलेक्टर आयुष प्रसाद ने मंगलवार को खरात के हथियार लाइसेंस को निलंबित करने का आदेश जारी किया। खरात, जो सिन्नर के मिरगांव का निवासी है, ने 15 अक्टूबर 2012 को एक रिवॉल्वर का लाइसेंस प्राप्त किया था, जिसे 1 जनवरी 2024 को नवीनीकृत किया गया था और यह दिसंबर 2028 तक वैध है।

ईंधन संकट | **नागरिकों को घबराने या पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें नहीं लगाने की अपील**

महाराष्ट्र में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक : सीएम

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र में ईंधन की कमी और 'ऊर्जा लॉकडाउन' की अफवाहों के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि नागरिक बेवजह घबराकर पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के पास अगले 30 दिनों के लिए पर्याप्त ईंधन का बैकअप मौजूद है। आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत से ज्यादा ईंधन स्टोर करने की प्रवृत्ति से कृत्रिम संकट पैदा हो सकता है।

केंद्र के फैसले से मिली राहत

केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती को मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'फ्यूल डिप्लोमेसी' की सराहना करते हुए कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत ने आम जनता को राहत देने का काम किया है।

पड़ोसी देशों से बेहतर स्थिति में भारत

फडणवीस ने कहा कि जहां कुछ पड़ोसी देशों में ईंधन संकट के कारण संस्थान बंद हो रहे हैं, वहीं भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती से संभाला है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय का परिणाम है।

गैस एजेंसियों पर सख्त निगरानी

राज्य सरकार ने गैस एजेंसियों और डीलरों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई एजेंसी कृत्रिम कमी पैदा करती है या अधिक कीमत वसूलती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कालाबाजारी या उपभोक्ताओं से अतिरिक्त पैसे वसूलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नागरिकों से अपील की गई है कि ऐसी किसी भी शिकायत की तुरंत सूचना प्रशासन को दें। सरकार ने आने वाले समय में भी ईंधन आपूर्ति बनाए रखने के लिए व्यापक योजना तैयार की है। प्रशासन अब उन लोगों पर भी नजर रख रहा है।

मीरा-भाईंदर का 'मेगा' बजट

4,585 करोड़ का ऐतिहासिक बजट मंजूर, विकास योजनाओं को रफ्तार

विनय दूबे | भाईंदर

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका (एमबीएमसी) की महासभा में वर्ष 2026-27 के लिए 4,585 करोड़ 17 लाख 82 हजार रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। यह बजट सत्तारूढ़ पक्ष ने अपने बहुमत के आधार पर पारित कराया। बजट में शहर के समग्र विकास, आय बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। नगरपालिका की विभिन्न विभागों से कुल आय 1,541 करोड़ 75 लाख 11 हजार रुपए निर्धारित की गई है, जबकि खर्च 1,541 करोड़ 41 लाख 20 हजार रुपए रखा गया है। इसके अलावा 2,578 करोड़ 84 लाख रुपए की शासन निधि भी विकास कार्यों के लिए प्रस्तावित है।

महासभा में संख्या बल से पास हुआ बजट

इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण पर जोर

इस बजट में बायोगैस और बायोमाइनिंग प्रोजेक्ट, अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम, डिजिटल क्लासरूम, स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार और नए मनपा मुख्यालय जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही पर्यावरण-अनुकूल गणेशोत्सव और कचरा प्रबंधन योजनाओं पर भी विशेष फोकस रखा गया है।

सत्तापक्ष का दावा: विकास का रोडमैप

स्थायी समिति के सभापति हसमुख गहलोत ने कहा कि यह बजट शहर की आधारभूत संरचना को मजबूत करेगा और मीरा-भाईंदर को डिजिटल व पर्यावरण-अनुकूल शहर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

स्वास्थ्य और शिक्षा को मिला बढ़ावा

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 55 करोड़ 48 लाख रुपए और शिक्षा के लिए 30 करोड़ 63 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आधुनिक एंबुलेंस सेवाएं और प्रस्तावित कैंसर अस्पताल जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं भी इस बजट का हिस्सा हैं।

घनकचरा प्रबंधन के लिए बड़ा प्रावधान

घनकचरा प्रबंधन के लिए 214 करोड़ 24 लाख 25 हजार रुपए और विशेष प्रकल्प के लिए 15 करोड़ 35 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। इससे शहर में स्वच्छता और कचरा निपटान व्यवस्था को मजबूत करने की योजना है।

विपक्ष का विरोध: चर्चा के बिना पास हुआ बजट

कांग्रेस के नगरसेवक व गटनेता जय ठाकुर ने बजट पारित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि भाजपा ने बहुमत के दम पर बजट पास कराया और विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने भूमिगत गटर योजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग भी उठाई।

आय के मुख्य स्रोत

महानगरपालिका की कुल आय 1,54,175.11 लाख रुपए है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा राजस्व अनुदान (32.23%) से आता है, जिसकी राशि 49,687.81 लाख रुपए है। इसके बाद नगर निगम करों (22.35%) से 34,462.16 लाख रुपए और शुल्क व उपयोगकर्ता शुल्क (21.62%) से 33,330.80 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। जलापूर्ति से 15.23% आय होती है, जबकि अन्य छोटे स्रोतों जैसे ब्याज (2.08%), अन्य आय (5.02%), निवेश (0.39%) और संपत्ति के किराये (0.78%) से शेष राशि प्राप्त होती है।

व्यय का लेखा-जोखा

महानगरपालिका का कुल खर्च 1,54,141.20 लाख रुपए दर्ज किया गया है। खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा रखरखाव और मरम्मत (25.04%) पर व्यय होता है, जो 38,592.67 लाख रुपए है। इसके बाद 'अ' बजट के तहत पूंजीगत खर्च (23.64%) का स्थान है। प्रशासनिक कार्यों और कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर क्रमशः 6.54% और 11.08% खर्च होता है। जलापूर्ति के रखरखाव (12.55%) और उससे संबंधित पूंजीगत कार्यों (5.88%) पर भी महत्वपूर्ण राशि खर्च की जाती है। अन्य खर्चों में ऋण भुगतान (4.02%), योजनाएँ (4.22%) और पेंशन (1.62%) शामिल हैं।

चरई में बिल्डरों की दबाव नीति पर बवाल

- विधायक केलकर ने दिए सख्त निर्देश
- पुरानी इमारतों से जबरन बेदखली का आरोप

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

ठाणे शहर के चरई इलाके में बिल्डरों द्वारा पुरानी इमारतों से लोगों को जबरदस्ती निकालने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस पर ठाणे विधायक संजय केलकर ने गंभीर रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

चरई की एक पुरानी इमारत के निवासियों ने खोपट स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित 'जनसेवकाचा जनसंवाद' कार्यक्रम के दौरान अपनी समस्याएं विधायक केलकर के सामने रखीं। केलकर ने बताया कि चरई ठाणे का पुराना इलाका है, जहां कई जर्जर इमारतें हैं, और डेवलपर्स इन्हें खतरनाक घोषित कर अधिकारियों के साथ मिलकर लोगों पर दबाव बना रहे हैं।

विधायक केलकर ने स्पष्ट कहा कि जब तक डेवलपर और रहवासियों के बीच उचित समझौता (एग्रीमेंट) नहीं होता, तब तक किसी भी निवासी पर घर खाली करने का दबाव नहीं डाला जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों के अधिकारों को हर हाल में सुरक्षित रखा जाए।

अस्थायी आवास में बदहाल स्थिति

विभिन्न योजनाओं से प्रभावित लोगों को प्रशासन द्वारा अस्थायी किराए के घर तो दिए गए हैं, लेकिन वहां सुविधाओं की कमी के कारण लोग बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। अब इन लोगों को किराए के घर खाली करने के नोटिस भी दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है।

जन आंदोलन की चेतावनी

विधायक केलकर ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर जल्द ही जन आंदोलन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम नागरिकों पर टैक्स वसूली के लिए मानसिक दबाव डालकर संपत्ति सील करने और पानी कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई की जा रही है, जबकि बड़े बकायेदार संस्थानों और डेवलपर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि आम लोग टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पेट्रोल-डीजल की खुली बिक्री पर रोक

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

सोशल मीडिया पर पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाहों के बीच जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए बोतल, कैन या किसी भी कंटेनर में फ्यूल बेचने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने पेट्रोलियम रूल्स 2002 के तहत आदेश जारी करते हुए सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया है कि पेट्रोल और डीज़ल केवल वाहनों के फ्यूल टैंक में ही दिया जाए, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना या कानून-व्यवस्था की स्थिति से बचा जा सके।

जारी आदेश के अनुसार, किसी भी ग्राहक को प्लास्टिक बोतल, कैन या अन्य कंटेनर में फ्यूल देना गैर-कानूनी होगा। साथ ही सभी पेट्रोल

पंपों पर 24 घंटे सीसीटीवी चालू रखना और बिक्री का नियमित रिकॉर्ड बनाए रखना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन पर पेट्रोलियम नियम 2002, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस व कंपनियों को दिए निर्देश

इस आदेश के पालन के लिए पुलिस विभाग को भी सक्रिय किया गया है। ठाणे, नवी मुंबई और मीरा-भायंदर के पुलिस आयुक्तों के साथ-साथ ठाणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के अधिकारियों को सभी पंपों पर पर्याप्त फ्यूल उपलब्ध कराने और आदेशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस फैसले में सहयोग करें।

ठाणे मनपा कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की किस्तें

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

मेयर शर्मिला पिंपलोलकर ने बजट बैठक में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मनपा के अधिकारियों और कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की तीसरी किस्त, जबकि परिवहन विभाग के कर्मचारियों को तीन किस्तें एक साथ दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर बकाया राशि का भुगतान 30 मार्च 2026 को कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के खातों में जमा कर दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।

मनपा में 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 12 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, पिछले छह वर्षों के वेतन अंतर की राशि पांच किस्तों में दी जानी है, जिसमें से दो किस्तें पहले ही जारी की जा चुकी हैं। शेष राशि के भुगतान में देरी को लेकर कर्मचारियों में असंतोष था, जिसे दूर करने के लिए तीसरी किस्त जारी करने की घोषणा की गई है।

लगातार फॉलोअप के बाद हुआ फैसला

मेयर पिंपलोलकर इस मुद्दे को लेकर आयुक्त सौरभ राव के साथ लगातार फॉलोअप कर रही थीं। इस फैसले से मनपा और परिवहन विभाग के कर्मचारियों व सेवानिवृत्त अधिकारियों में संतोष का माहौल है। कर्मचारियों ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मेयर, डिप्टी मेयर कृष्णा पाटिल और आयुक्त सौरभ राव के प्रति आभार व्यक्त किया है।

13 साल, कई सरकारें, पर जादू-टोना कानून की नियमावली अब भी गायब

भाजपा विधायक बडोले ने अपनी ही सरकार को घेरा, अंधविश्वास के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र में जादू-टोना विरोधी कानून (2013) के पारित होने के 13 साल बाद भी इसकी 'नियमावली' तैयार न हो पाना अब एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। भाजपा विधायक राजकुमार बडोले द्वारा अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने से राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है, वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर तीखा पलटवार किया है। भाजपा विधायक राजकुमार बडोले ने विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए कहा कि साल 2013 में कानून पारित होने के बावजूद अब तक इसकी नियमावली नहीं बनी है। उन्होंने बेबाकी से कहा कि चाहे भाजपा की सरकार रही हो या महाविकास आघाड़ी की, किसी ने भी इस पर ठोस काम नहीं किया। उनकी मांग है कि अंधविश्वास फैलाने वालों पर लगाम कसने के

लिए इसे तुरंत लागू किया जाए। बडोले ने तर्क दिया कि यदि इस कानून की नियमावली स्पष्ट होती, तो राज्य में अंधविश्वास के कारण होने वाली घटनाओं और अशोक खरात जैसे मामलों को समय रहते रोका जा सकता था। उन्होंने सरकारों से अपील की कि वे 'निजी हितों' और वोट बैंक से ऊपर उठकर समाज सुधार के इस काम को प्राथमिकता दें।

कांग्रेस का तीखा हमला

कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने भाजपा पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने जानबूझकर इस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राज्य में 'जादू-टोना की ही सरकार' आ गई है, इसलिए वे इसे लागू नहीं करना चाहते। लोंढे ने इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया।

गैस किल्लत पर वसई में बवाल मुंबई-अहमदाबाद हाईवे जाम

ओपी यादव | वसई

वसई पूर्व के बर्मा सेल इलाके में गैस की किल्लत से परेशान सैकड़ों मजदूर और कामगार शुक्रवार को सड़कों पर उतर आए। 5 किलो के गैस सिलेंडर लेकर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पहले 5 किलो का सिलेंडर करीब 480 रुपए में रिफिल हो जाता था, लेकिन अब गैस मिलना लगभग बंद हो गया है। जहां गैस उपलब्ध है, वहां 1000 रुपए या उससे अधिक कीमत वसूली जा रही है,

सैकड़ों मजदूर सड़कों पर उतरे

जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार, बर्मा सेल इलाके में गैस वितरण की अफवाह फैलने के बाद सैकड़ों लोग वहां पहुंच गए। जब एजेंसी कर्मचारियों ने गैस उपलब्ध नहीं होने की बात कही, तो लोगों का गुस्सा भड़क गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

हाईवे जाम से यातायात ठप

गुस्साए मजदूर मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर पहुंच गए और खाली सिलेंडर सड़क पर रखकर दोनों लेन जाम कर दी। इसके चलते वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। कुछ जगहों पर वाहन चालकों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी सामने आईं। सूचना मिलते ही पुलिस और ट्रैफिक विभाग मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात काबू में लाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बाद में भीड़ को हटाकर यातायात बहाल किया गया। वहीं तहसीलदार दीपक गायकवाड़ ने गैस आपूर्ति जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मीरा भाईंदर में बुलडोजर बनाम डेकोरेटर्स

आगजनी के बाद अवैध गोदामों पर हंटर

- महापौर डिंपल मेहता से मिले व्यापारी
- डेकोरेटर्स एसोसिएशन ने विशेष योजना की लगाई गुहार

डीबीडी संवाददाता | भाईंदर

24 मार्च को मीरा रोड के प्लेज़ेंट पार्क में हुई भीषण आगजनी की घटना से सबक लेते हुए मीरा-भाईंदर महानगरपालिका (एमबीएमसी) ने अवैध निर्माणों पर सख्ती शुरू कर दी है। मनपा का 'शांत' बुलडोजर अब सक्रिय हो गया है, जिससे स्थानीय डेकोरेटर्स और कैटरर्स में हड़कंप मच गया है। तोड़फोड़ कार्रवाई के डर से परेशान मीरा-भाईंदर

डेकोरेटर्स एंड कैटरर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने महापौर डिंपल मेहता और अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे को निवेदन सौंपकर राहत की अपील की है।

मनपा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मंडप डेकोरेटर्स सक्रिय हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर मनपा के दस्तावेजों में किसी विशेष योजना का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। एसोसिएशन ने प्रशासन से इस दिशा में ठोस योजना बनाने का अनुरोध किया है। एसोसिएशन के अनुसार, मीरा-भाईंदर के विभिन्न वार्डों में मंडप डेकोरेटर्स के साथ-साथ लॉन और ग्राउंड कीपर भी काम करते हैं। इन कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री को रखने के लिए अस्थायी गोदाम बनाए जाते हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा, 'कोरोना काल में हमारा व्यवसाय दो-तीन साल तक ठप रहा। अब धीरे-धीरे उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई से सैकड़ों परिवारों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है।'

संभावित सुरक्षा योजना क्या हो सकती है?

विशेषज्ञों के अनुसार, आवासीय इलाकों से 30 से 50 मीटर की दूरी, अनिवार्य सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षा प्रमाणपत्र, अग्निरोधी सामग्री का उपयोग, थर्मल स्कैनिंग और सीमित आकार के मंडप जैसी शर्तें लागू की जा सकती हैं। इसके अलावा, सब्सिडी पर सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराने जैसी योजना भी बनाई जा सकती है, जिससे डेकोरेटर्स को लाभ मिले और नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। मनपा के एक अधिकारी ने बताया कि आगजनी की घटना के बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है।

कार्रवाई हो, लेकिन व्यापारियों को राहत भी मिले

निवेदन में मनपा से मांग की गई है कि अवैध डेकोरेटर्स और लॉन-ग्राउंड संचालकों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, लेकिन वैध व्यापारियों को राहत दी जाए। एसोसिएशन ने कहा कि हम भी आगजनी की घटना से आहत हैं, लेकिन यह भी सच है कि इस उद्योग पर सैकड़ों परिवार निर्भर हैं। इसलिए प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा है। महापौर डिंपल मेहता को ज्ञापन सौंपने के बाद एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। मंडप सजावट में आग लगना, ढांचा गिरना या बिजली से जुड़े हादसे आम हैं। इसके बावजूद सुरक्षा मानकों की अनदेखी चिंता का विषय बनी हुई है। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मनपा को मंडप डेकोरेटर्स के लिए एक विशेष नीति बनानी चाहिए, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके और व्यवसाय को व्यवस्थित किया जा सके।

एलपीजी कमी के बीच केरोसिन वितरण का फैसला

हर परिवार को 3 लीटर का कोटा तय

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात के चलते एलपीजी गैस की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने अस्थायी विकल्प के रूप में केरोसिन वितरण को मंजूरी दी है। 12 मार्च 2026 के आदेश के तहत महाराष्ट्र को 37.44 लाख लीटर केरोसिन आवंटित किया गया है, जिसमें ठाणे जिले को 48,000 लीटर का हिस्सा मिला है। यह कदम आम लोगों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

किन्हें मिलेगा लाभ, क्या हैं नियम?

जिला प्रशासन के अनुसार, यह सुविधा मुख्य रूप से अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउसहोल्ड राशन कार्ड धारकों के लिए होगी। जरूरत और उपलब्धता के आधार पर व्हाइट राशन कार्ड धारकों को भी शामिल किया जा सकता है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वे ग्राम पंचायत का निवास प्रमाण पत्र देकर केरोसिन प्राप्त कर सकेंगे, जबकि प्रवासी मजदूर भी सरकारी पहचान पत्र दिखाकर इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।

हर परिवार को 3 लीटर, तय प्रक्रिया

प्रत्येक पात्र परिवार को 3 लीटर केरोसिन दिया जाएगा। इसका वितरण अधिकृत फेयर प्राइस दुकानों और लाइसेंसधारी विक्रेताओं के माध्यम से किया जाएगा। जिन गांवों में विक्रेता उपलब्ध नहीं हैं, वहां के लोगों को नजदीकी गांव से केरोसिन लेना होगा। जिले के लिए स्वीकृत स्टॉक के परिवहन हेतु चार टैंकर लगाए गए हैं और मार्च-अप्रैल 2026 के दौरान मांग के अनुसार तहसील स्तर पर वितरण किया जाएगा। प्रशासन ने संकेत दिया है कि केरोसिन की कीमत को लेकर जल्द अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

न्यूज़ ब्रीफ

विद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश तिथि 31 मार्च तक

मुंबई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत प्राइवेट अनएडेड स्कूलों में 25 % आरक्षण प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अब 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी गई है। यह बढ़ोतरी अभिभावकों को आवेदन जमा करने और ज़रूरी संशोधन करने के लिए अधिक समय देने के मकसद से दिया गया है। जैसा कि पहले बताया गया था, विद्यार्थियों के पालकों के लिए 3 से 5 किमी की दूरी के अंदर विद्यालय चुनने की सुविधा बनाए रखी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के निर्देशों के मुताबिक, स्कूल की दूरी के बारे में 1 किमी की दूरी की शर्त में ढील दी गई है, जिससे पालकों के लिए ज़्यादा स्कूल विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। साथ ही, जिन पालकों ने पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर दी है, उनके लिए पोर्टल पर 'अनकन्फर्मिंग' और 'कन्फर्मिंग' की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि दरखास्त में ज़रूरी सुधार किए जा सकें। पोर्टल पर पॉप-अप नोटिफिकेशन के ज़रिए पालकों को इसकी जानकारी दी जा रही है।

मंत्री नरहरि झिरवल के वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा : मुख्यमंत्री

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को मुंबई में कहा कि मंत्री नरहरि झिरवल के विरुद्ध सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए वीडियो की जांच के बाद सत्यता आने पर कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आज कहा कि सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद आज नरहरि झिरवल ने उन्हें फोन पर कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। झिरवल ने कहा है कि यह वीडियो कई वीडियो को मिलाकर बनाया गया है। इसलिए वीडियो किसने बनाया, इसकी जांच कर सच्चाई जनता के समक्ष आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद उन्होंने नरहरि झिरवल को इस मामले की शिकायत पुलिस के समक्ष करने के लिए कहा है। शिकायत के बाद इस वीडियो के बारे में विस्तृत जांच की जाएगी। जांच में जो भी सामने आएगा, उस पर मैं और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार साथ में मिलकर निर्णय लेंगे।

अंधेरी ईस्ट के औद्योगिक एस्टेट की दो मंजिला इमारत में भीषण आग

मुंबई। अंधेरी ईस्ट स्थित महाकाली केव्स रोड पर 'नंद भवन इंडस्ट्रियल एस्टेट' की एक दो मंजिला इमारत में शुक्रवार शाम करीब 4:41 बजे भीषण आग लग गई। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अनुसार, आग इमारत की भूतल और पहली मंजिल पर लगी, जिसके बाद पूरे परिसर में धुएं का गुबार छा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शाम 5:08 बजे इसे 'लेवल 2' की आग घोषित किया गया। मुंबई फायर ब्रिगेड ने कई दमकल गाड़ियों और वाटर टैंकरों के साथ बचाव कार्य शुरू किया, जिसमें पुलिस, बिजली विभाग और एम्बुलेंस सेवाओं ने भी सहयोग दिया। राहत की बात यह है कि इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

विधान भवन की फर्जी प्रवेश पत्रिका देने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई में विधान सभा के बजट सत्र के दौरान फर्जी प्रवेश पत्रिका के जरिए विधान भवन में घुसने के मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में मरीन ड्राइव पुलिस ने शुक्रवार को पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मंत्रालय और विधान भवन से जुड़े कर्मचारी भी शामिल हैं।

मुख्य आरोपी ने खुद को बताया मुख्यमंत्री कार्यालय का सलाहकार

जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी दत्तात्रेय गुंजाल (53) ने फर्जी प्रवेश पत्रिका पर खुद को मुख्यमंत्री कार्यालय का सलाहकार दर्शाया था। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपितों में चपरासी गणपत भाऊ जवाले (50), नागेश शिवाजी पाटिल (42), क्लर्क मनोज आनंद मोरबले (40) और स्वप्निल रमेश तायडे (40) शामिल हैं।

मंत्रालय और विधान भवन के कर्मचारी भी शामिल

पुलिस के अनुसार इस फर्जीवाड़े में मंत्रालय के दो और विधान भवन के दो कर्मचारी शामिल पाए गए हैं। वहीं, मंत्रालय के महेश डुमपलवार और लवेश शंकर नकाटे फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। मामले की गहन जांच मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन की टीम कर रही है।

फर्जी पास 2000 से 5000 रुपये में बेचे जाने का आरोप

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब विधायक अमोल मिटकरी ने विधानसभा में फर्जी पास बेचे जाने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने बताया था कि 2000 से 5000 रुपये में फर्जी प्रवेश पत्रिका बेची जा रही थीं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए।

सुरक्षा सख्ती के बीच बड़ा सुरक्षा उल्लंघन

उल्लेखनीय है कि हाल ही में विधान भवन को बम की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। इसके बावजूद फर्जी पास के जरिए घुसपैठ का मामला सामने आना सुरक्षा में बड़ी चूक को दर्शाता है। उद्योग मंत्री उदय सामंत के निर्देश पर शुरू हुई जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।

गोरेगांव पर्ल प्रोजेक्ट घोटाला

ईडी ने 41.70 करोड़ की संपत्तियां अटैच कीं

पीएमएलए के तहत कार्रवाई, फ्लैट-दुकानें जब्त

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुंबई जोनल कार्यालय ने 25 मार्च 2026 को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 41.70 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। ये संपत्तियां मुंबई के गोरेगांव स्थित 'गोरेगांव पर्ल CHS' प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं, जिनमें पूर्ण और आंशिक रूप से निर्मित रिहायशी फ्लैट, कमर्शियल दुकानें और ऑफिस स्पेस शामिल हैं।

डेवलपर पर खरीदारों से धोखाधड़ी का आरोप

ईडी की जांच में सामने आया कि इन संपत्तियों का विकास M/s साई सिद्धि डेवलपर्स द्वारा किया गया था। डेवलपर ने फ्लैट और दुकानों का हिस्सा बाहरी खरीदारों को बेचकर उनसे पूरी या आंशिक रकम वसूल ली, लेकिन न तो उन्हें कब्जा दिया गया और न ही पैसे लौटाए गए, जिससे खरीदारों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ।

जयेश तन्ना पर 'प्रोसीड्स ऑफ क्राइम' का आरोप

जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि साई सिद्धि डेवलपर्स के प्रमुख पार्टनर जयेश तन्ना ने खरीदारों से धोखाधड़ी कर जो रकम हासिल की, वही इस मामले में 'प्रोसीड्स ऑफ क्राइम' मानी गई है। आरोप है कि इस धन का उपयोग निजी लाभ के लिए किया गया।

मुंबई पुलिस की FIR के आधार पर कार्रवाई

ईडी ने यह कार्रवाई मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू की, जो IPC की विभिन्न धाराओं के तहत साई सिद्धि डेवलपर्स, जयेश तन्ना और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई थीं। इन मामलों में पुलिस चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। जांच में सामने आया कि गोरेगांव पर्ल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर जुटाए गए फंड का दुरुपयोग किया गया, जिससे प्रोजेक्ट अधूरा रह गया और खरीदारों को करीब 47.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

पूर्व महापौर श्रद्धा जाधव के पति और शिवसेना नेता श्रीधर जाधव का निधन

मुंबई। शिवसेना (ठाकरे) के संगमेश्वर संपर्क प्रमुख और पूर्व महापौर श्रद्धा जाधव के पति श्रीधर मुकुंद जाधव (65) का संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 'मनोहर डेकोरेटर्स' के संचालक और एक प्रतिष्ठित मराठी उद्योजक व समाजसेवक के रूप में जाने जाते थे। उनके पार्थिव शरीर को भोईवाड़ा स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहाँ शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार को सांत्वना दी। शुक्रवार शाम भोईवाड़ा श्मशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सुनील प्रभु, सचिन अहीर, मिलिंद नार्वेकर और अजय चौधरी सहित भारी संख्या में शिवसैनिक और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

राज्य दिव्यांग निधि को मिली मंजूरी

- 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले लोगों को मिलेगा सीधा लाभ
- तुकाराम मुंढे संभालेंगे कोष की कमान

दीपक पवार | मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांगों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और संवेदनशील कदम उठाते हुए 'राज्य दिव्यांग निधि' स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-88 के तहत गठित यह कोष, सरकारी योजनाओं में धन की कमी को दूर करने और दिव्यांगों के पुनर्वसन के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार बनेगा। राज्य सरकार ने इस विशेष निधि के लिए शुरुआती निवेश के रूप में 20 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। यह राशि उन स्थितियों में इस्तेमाल की जाएगी जब किसी सरकारी योजना, महामंडल या स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका/पंचायत) के पास दिव्यांगों के कल्याण के लिए फंड कम पड़ जाएगा।

कहाँ से आएगा पैसा?

यह निधि केवल सरकारी अनुदान तक सीमित नहीं रहेगी। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के पास प्राप्त होने वाला अनुदान, उपहार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि, दान, समेत अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होने वाली सभी राशि राज्य दिव्यांग निधि का हिस्सा मानी जाएगी। इस कोष के माध्यम से कुष्ठरोग मुक्त, कम दृष्टि, मस्तिष्क पक्षाघात (Cerebral Palsy), नेत्रहीनता समेत कुल 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। राज्य दिव्यांग निधि के सही प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए एक नियामक मंडल का गठन किया गया है। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के सचिव तुकाराम मुंढे इसके अध्यक्ष होंगे।

जमाखोरी के लिए उकसा रहे राऊत : बन

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन ने शिवसेना नेता संजय राऊत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे ईंधन और गैस की कमी को लेकर जनता में डर का माहौल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राऊत और विपक्षी दल गलत खबरें फैलाकर लोगों को ईंधन और गैस की जमाखोरी के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे अराजकता की स्थिति बन रही है।

नवनाथ बन ने स्पष्ट किया कि भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है और देश के पास करीब दो महीने का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारतीय जहाजों को हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से ईंधन लाने की अनुमति मिल रही है, इसलिए जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है।

ईरान-इजराइल युद्ध के बीच राहत उपाय

उन्होंने कहा कि ईरान-इजराइल युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें युद्धस्तर पर राहत कार्य कर रही हैं। महायुती सरकार ने राशनकार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 3 लीटर रॉकेल देने का निर्णय लिया है, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज

नवनाथ बन ने संजय राऊत पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार का विरोध करते हैं और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राऊत राहत उपायों को भी राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनका "वैचारिक दिवालियापन" सामने आता है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

केजी बेसिन गैस विवाद

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने आंध्र प्रदेश के तट से दूर कृष्णा-गोदावरी बेसिन में स्थित ओएनजीसी के कुओं से बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का अवैध दोहन किया।

कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका को किया निरस्त

मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे (यहां संशोधन: मूल पाठ में नाम भिन्न हो सकता है) और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ के समक्ष जितेंद्र पी. मारू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से सीबीआई और केंद्र सरकार को मामले में आपराधिक कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया।

2004-2013 के बीच 'तिरछी ड्रिलिंग' का आरोप

याचिका में दावा किया गया था कि 2004 से 2013 के बीच रिलायंस ने अपने गहरे समुद्री कुओं से तिरछी ड्रिलिंग कर पास के ओएनजीसी कुओं तक पहुंच बनाई और वहां से अवैध रूप से गैस निकाली। ओएनजीसी अधिकारियों को 2013 में इस कथित गड़बड़ी का पता चला था, जिसके बाद केंद्र सरकार को इसकी जानकारी दी गई थी।

स्वतंत्र जांच और समिति ने नुकसान का किया आकलन

डी. गोलियर एंड मैकनॉटन (D&M) की स्वतंत्र जांच में कथित अनियमितताओं की पुष्टि होने का दावा किया गया था। इसके बाद ए.पी. शाह समिति ने कथित तौर पर निकाली गई गैस की कीमत 1.55 अरब डॉलर से अधिक आंकी, जिसमें ब्याज भी शामिल था। इससे पहले रिलायंस को इस मामले में मध्यस्थता में राहत मिली थी, लेकिन 14 फरवरी 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील स्वीकार करते हुए उस फैसले को रद्द कर दिया था और इसे सार्वजनिक नीति के खिलाफ माना था। याचिका में यह भी कहा गया था कि कथित साजिश मुंबई में रची गई, इसलिए सीबीआई को जांच का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया।

भरणे ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज से मुलाकात की

किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा

मुंबई/नई दिल्ली। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने शुक्रवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर राज्य के कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में कृषि प्रगति, लंबित योजनाओं और किसानों के हितों को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। भरणे ने राज्य में कृषि मशीनीकरण और ड्रिप सिंचाई योजनाओं को तेज करने के लिए केंद्र से अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कोंकण में फसलों के नुकसान का मुद्दा उठाया

बैठक के दौरान भरणे ने कोंकण और तटीय क्षेत्रों में बेमौसम बारिश से आम और काजू की फसलों को हुए भारी नुकसान की जानकारी दी। इस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार की टीम ने नुकसान का निरीक्षण किया है और किसानों को राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित किसानों को 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। भरणे ने राज्य में अधिक प्याज उत्पादन का हवाला देते हुए एपीएमसी के माध्यम से सीधे खरीद की मांग की। इस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक विचार करने और किसानों के हित में उचित निर्णय लेने का भरोसा दिया।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
कासरगोड न्यायालय में
ओ.पी. (एम.वी.) संख्या 140/2023
बीच में:
हनीफा बी एवं अन्य याचिकाकर्ता/
याचिकाकर्ता और **गोरख सरदार एवं अन्य**
प्रतिवादी/प्रतिवादी
प्रथम प्रतिवादी को नोटिस

गोरख सरदार, आयु 52 वर्ष, पिता धंधू सरदार, निवासी: ऑपोज़िट म्युनिसिपल ऑफिस, उल्हासनगर 3, उल्हासनगर, ठाणे (ग्रामीण), महाराष्ट्र, भारत - 421003 कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त मामला आपकी उपस्थिति हेतु दिनांक 04-04-2026 को प्रातः 11:00 बजे उक्त न्यायालय के समक्ष नियत किया गया है। यदि आप उस दिन उपस्थित होने में असफल रहते हैं, तो मामले की सुनवाई कर उसे एकपक्षीय (Exparte) रूप से निर्णयित किया जाएगा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कासरगोड के आदेश से।

हस्ता/-
अब्दुल निज़ार एम.ए.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

कासरगोड
दिनांक: 25.03.2026

मध्य रेल
वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ई-निविदाएं

ई-निविदा सूचना क्रमांक: NIT/01/26/15 दिनांक 26.04.2026 भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से, प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, मध्य रेलवे निम्नलिखित वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं:

क्र.	निविदा क्र.	विविवरण	मात्रा	नियत तिथि
1	38265007	उच्च क्षमता वाली एयर स्प्रिंग असेंबली 180KN	168 नग	20 अप्रैल 26
2	27263239	सस्पेंशन ट्यूब बेयरिंग	1322 सेट	20 अप्रैल 26
3	27261020	बेयरिंग ब्रैकेट का सेट	105 सेट	20 अप्रैल 26
4	38263034	वर्टीकल अनुप्रयोग के लिए 600 किलोग्राम क्षमता वाला डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर	3582 नग	27 अप्रैल 26
5	42263685	KBIL के लिए वस्तुओं का सेट	15 सेट	23 अप्रैल 26
6	71265009	सभी रोलिंग स्टॉक (लोको, कोच और वैगन) के जाम हुए रोलर बेयरिंग पहियों के लिए व्हील स्केट ट्रॉली	08 नग	20 अप्रैल 26
7	38261885	मालगाड़ियों के लिए नॉन-एस्बेस्टस L-टाइप कंपोजीशन ब्रेक, RDSO ड्राइंग नंबर WD-99062-S-01, Alt-4 के अनुसार। सामग्री और स्पेसिफिकेशन्स, अप्रैल 2019 के RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर WD-13-ABR-2019	58112 नग	04 मई 26
8	43261147	4.5 kW का ब्रशलेस अल्टरनेटर	65 नग	24 अप्रैल 26
9	43261135	110V AC 450mm स्वीप फिक्स्ड टाइप कैरिज फैन	4234 नग	20 अप्रैल 26
10	42263712	वंदे भारत का प्राथमिक वर्टीकल डैम्पर	634 नग	22 अप्रैल 26
11	18262209	ट्रैक्शन मोटर सस्पेंशन रोलर बेयरिंग	105 सेट	20 अप्रैल 26
12	27263334	बुल गियर 72 टीथ	382 नग	20 अप्रैल 26

नोट : उपरोक्त सभी निविदाएं ई-निविदाएं हैं और सभी निविदाकारों से अनुरोध है कि वे अपनी बोलियां IREPS वेबसाइट https://www.ireps.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा करें। उपर्युक्त निविदाओं और अन्य आपूर्ति निविदाओं के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया IREPS वेबसाइट पर जाएं।

अनाधिकृत रूप से रेल लाइन को पार करना दंडनीय अपराध है।

1034

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण
बांधकाम विभाग
-: शुध्दीपत्रक :-
निविदा सूचना क.५४/२०२५-२६

सदरची निविदा दि.२०/०३/२०२६ रोजी वर्तमानपत्रात व शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर निविदेत खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे.

अ.	प्रसिध्द झालेला मजकूर	वाचण्यात येणारा मजकूर
1.	कोरे निविदा फॉर्म व निविदेबाबतच्या सर्व अटी शर्तीची संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या www. mahatenders.Gov. in या संकेतस्थळावर दि.२०/०३/२०२६ ते दि.२७/०३/२०२६ रोजी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत उपलब्ध होईल. भरण्यात आलेल्या निविदा दि.२७/०३/२०२६ रोजी दुपारी ३.०० वाजेपर्यत वरील संकेतस्थळावर अपलोड करणेत याव्यात. प्राप्त निविदा दि.३०/०३/२०२६ रोजी दुपारी ४.०० वाजता शक्य झाल्यास उघडण्यात येतील.	कोरे निविदा फॉर्म व निविदेबाबतच्या सर्व अटी शर्तीची संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या www. mahatenders.Gov.in' या संकेतस्थळावर दि.२०/०३/२०२६ ते दि.२/०४/२०२६ रोजो दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत उपलब्ध होईल. भरण्यात आलेल्या निविदा दि.२/०४/२०२६ रोजी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत वरील संकेतस्थळावर अपलोड करणेत याव्यात. प्राप्त निविदा दि.६/०४ २०२६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता शक्य झाल्यास उघडण्यात येतील.

या व्यतिरिक्त सदर निविदा अटी शर्तीमध्ये इतर कोणताही बदल केलेला नाही.

जा क्र/ कडोंमपा/जसंवि। मुका /१०३६
दिनांक-27/03/2026

सही/-
शहर अभियंता
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण.

संपादकीय

कानूनी बेड़ियों से मुक्ति की ओर बढ़ता भारत

भारतीय न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे में सुधार की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और साहसिक कदम उठाया है। लोकसभा में पेश किया गया 'जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026' केवल एक विधायी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह देश के 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (कारोबार करने की सुगमता) और 'ईज ऑफ लिविंग' (जीवन जीने की सुगमता) के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस विधेयक के माध्यम से 23 मंत्रालयों से जुड़े 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें से 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना एक क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। विधेयक का मुख्य दर्शन 'भरोसे पर आधारित शासन' है। आजादी के बाद से भारत में कई ऐसे कानून बने रहे, जिनमें छोटी-छोटी तकनीकी चूक या अनजाने में हुई प्रशासनिक गलतियों के लिए जेल की सजा का प्रावधान था। उदाहरण के तौर पर, किसी कंपनी द्वारा समय पर कोई रिपोर्ट दाखिल न कर पाना या किसी मामूली मानक का उल्लंघन करना भी आपराधिक मामला बन जाता था। ऐसे प्रावधान न केवल उद्यमियों में भय का माहौल पैदा करते थे, बल्कि इससे अदालतों पर भी मुकदमों का बोझ बढ़ता था। अब इन छोटी गलतियों पर जेल की सजा के बजाय केवल जुर्माने का प्रावधान करना, देश में 'इंस्पेक्टर राज' के अवशेषों को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी जीत है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में सजा और जुर्माने को अपराध की गंभीरता के अनुरूप संतुलित किया गया है। 2023 के मूल जन विश्वास कानून की सफलता के बाद, इस दूसरे संस्करण का दायरा काफी विस्तृत है। 19 मंत्रालयों से बढ़कर अब 23 मंत्रालयों को इसमें शामिल करना यह दर्शाता है कि सरकार प्रशासन के हर स्तर पर 'अपराधमुक्ति' चाहती है। इससे न केवल विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, बल्कि घरेलू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को भी कानूनी पेचीदगियों से बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, लोकतंत्र की खूबसूरती इसके विरोध और विमर्श में निहित है। कांग्रेस सांसदों कडियम काव्या और जीके पदवी द्वारा उठाए गए सवाल महत्वपूर्ण हैं। विपक्ष का यह तर्क कि यह विधेयक मनमाना है और इससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है, एक गंभीर चिंता की ओर इशारा करता है। विपक्ष की आशंका है कि दंड के प्रावधानों को हल्का करने से नियम तोड़ने वालों को बढ़ावा मिल सकता है। चयन समिति को इसे फिर से भेजने की मांग यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सुधारों की आड़ में कहीं जवाबदेही खत्म न हो जाए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि 'अपराध की श्रेणी से हटाना' और 'नियमों की अनदेखी' के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची जाए। सरकार का पक्ष स्पष्ट है कि केवल 'तकनीकी और छोटे' अपराधों को ही बदला जा रहा है, गंभीर और जनहित से जुड़े अपराधों को नहीं। अपील करने की व्यवस्था बनाना और जुर्माने को तर्कसंगत बनाना यह सुनिश्चित करता है कि न्याय प्रक्रिया पारदर्शी रहे। यह विधेयक 2025 में पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए प्रारंभिक प्रारूप और चयन समिति की सिफारिशों का परिष्कृत रूप है। निष्कर्षतः, 'जन विश्वास विधेयक, 2026' भारतीय कानूनी प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप ढालने का प्रयास है। किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए यह अनिवार्य है कि उसके नागरिक और व्यापारी कानूनी जाल में उलझने के बजाय नवाचार और विकास पर ध्यान केंद्रित करें। यदि इस विधेयक को सही भावना के साथ लागू किया गया और विपक्ष द्वारा उठाई गई चिंताओं का प्रशासनिक स्तर पर समाधान निकाला गया, तो यह भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को पंख देने में मील का पत्थर साबित होगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत पर मंडराता संकट

आलोक सिंह
अपर जिला सहकारी अधिकारी
तहसील ऊंचाहार
जनपद रायबरेली

रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँचने का भारत का एकमात्र वैकल्पिक मार्ग है। युद्ध की स्थिति में यह पूरी परियोजना अधर में लटक जाएगी, जिससे भारत के क्षेत्रीय व्यापारिक हितों को भारी चोट पहुँचेगी। साथ ही, भारत का 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' (INSTC) भी खतरे में पड़ जाएगा, जो रूस और यूरोप तक व्यापार का एक सस्ता मार्ग प्रदान करता है।

आज का विश्व एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहाँ कूटनीति की मेज छोटी होती जा रही है और युद्ध के नगाड़े तेज सुनाई दे रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव केवल दो देशों का सैन्य गतिरोध नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक आर्थिक और मानवीय सुनामी की आहट है। यदि यह तनाव पूर्ण युद्ध में तब्दील होता है, तो इसके आंकड़े और परिणाम इतने भयावह होंगे कि आधुनिक सभ्यता को अपनी प्रगति की दिशा बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। युद्ध का सबसे पहला और घातक प्रहार वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर होगा, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और 25% एलएनजी (LNG) 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' से होकर गुजरता है। ईरान की ओर से इस मार्ग को बंद करने की एक भी कोशिश कच्चे तेल की कीमतों को 150 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुँचा सकती है, जिससे वैश्विक जीडीपी में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी और दुनिया 1970 के दशक जैसी महामंदी की चपेट में आ जाएगी।

भारत के लिए यह संकट द्विआधारी मार जैसा है, क्योंकि देश अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा आयात करता है। आर्थिक आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कच्चे तेल की कीमतों में प्रति बैरल महज 10 डॉलर की बढ़ोतरी भारत के 'चालू खाता घाटे' (CAD) को लगभग 12-15 अरब डॉलर तक बढ़ा देती है। इससे भारतीय रुपये का मूल्य तेजी से गिरेगा, जिससे न केवल पेट्रोल और डीजल बल्कि माल ढुलाई महंगी होने के कारण हर बुनियादी वस्तु की कीमत आसमान छूने लगेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना एक असंभव चुनौती बन जाएगा, जिसका सीधा प्रहार देश की विकास दर और आम नागरिक की बचत पर पड़ेगा। यह आर्थिक अस्थिरता घरेलू निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी।

आर्थिक क्षति के साथ-साथ, भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय खाड़ी देशों में रहने वाले लगभग 90 लाख भारतीय प्रवासी हैं। ये नागरिक न केवल भारत के सांस्कृतिक दूत हैं, बल्कि वे हर साल लगभग 80-85 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा (Remittances) भारत भेजते हैं, जो देश के विदेशी मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। युद्ध छिड़ने की स्थिति में इन नागरिकों की सुरक्षा और उनकी घर वापसी सर्वोपरि चुनौती होगी। 1990 के कुवैत संकट के दौरान भारत ने 1,70,000 नागरिकों को निकाला था, जो उस समय का सबसे बड़ा हवाई रेस्क्यू था, लेकिन आज प्रवासियों की यह विशाल संख्या किसी भी निकासी अभियान को अत्यंत जटिल और खर्चीला बना देगी। इसके अलावा, इन प्रवासियों के रोजगार छिनने से भारत के भीतर बेरोजगारी का दबाव भी अचानक बढ़ जाएगा।

रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँचने का भारत का एकमात्र वैकल्पिक मार्ग है। युद्ध की स्थिति में यह पूरी परियोजना अधर में लटक जाएगी, जिससे भारत के क्षेत्रीय व्यापारिक हितों को भारी चोट पहुँचेगी। साथ ही, भारत का 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' (INSTC) भी खतरे में पड़ जाएगा, जो रूस और यूरोप तक व्यापार का एक सस्ता मार्ग प्रदान करता है। भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती यह होगी कि वह अपने पुराने मित्र ईरान और प्रमुख रणनीतिक साझेदार अमेरिका के बीच संतुलन कैसे बनाए रखे, क्योंकि किसी भी एक पक्ष का समर्थन करना भारत के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। भविष्य के सुरक्षा परिदृश्य को देखें तो यह संघर्ष 'परमाणु अप्रसार' के वैश्विक प्रयासों को पूरी तरह विफल कर सकता है। यदि ईरान अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ता है, तो सऊदी अरब और तुर्की जैसे पड़ोसी देश भी इसी होड़ में शामिल हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की रिपोर्टों के अनुसार, परमाणु केंद्रों पर संभावित सैन्य हमले न केवल कूटनीतिक विफलता होंगे, बल्कि उनसे होने वाला रेडियोधर्मी रिसाव आने वाली कई पीढ़ियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुँचाएगा। मध्य पूर्व, जो पहले से ही सीरिया और यमन जैसे संघर्षों के घाव झेल रहा है, पूरी तरह से एक परमाणु बारूद के ढेर में तब्दील हो जाएगा, जिससे वैश्विक शांति का ढांचा चरमरा जाएगा।

अंततः, इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी भी अंतिम विजेता तय नहीं करता, वह केवल विनाश का विस्तार करता है। ईरान-अमेरिका संघर्ष का वास्तविक समाधान मिसाइलों या प्रतिबंधों में नहीं, बल्कि कूटनीति की मेज पर ही संभव है। वैश्विक शक्तियों और संयुक्त राष्ट्र को अपनी निष्क्रियता त्यागकर सक्रिय मध्यस्थता करनी होगी। भारत जैसे बढ़ते वैश्विक प्रभाव वाले देश को अपनी 'सॉफ्ट पावर' का उपयोग कर दोनों पक्षों को बातचीत के लिए प्रेरित करना होगा। यदि आज विवेक काम नहीं आया, तो भविष्य का इतिहास हमें एक ऐसी पीढ़ी के रूप में याद रखेगा जिसने उपलब्ध संसाधनों और तकनीक का उपयोग विकास के बजाय स्वयं के विनाश के लिए किया। शांति केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि इस परमाणु युग में मानवता के अस्तित्व की अनिवार्य शर्त है।

शख्सियत — शिवाजी गणेशन

अभिनय के सम्राट

शिवाजी गणेशन का जीवन भारतीय सिनेमा के इतिहास में संघर्ष, समर्पण और असाधारण प्रतिभा का प्रेरक उदाहरण है। उनका जन्म 28 मार्च 1928 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका वास्तविक नाम विलुप्पुरम चिन्नैया मणियार गणेशन था, लेकिन अभिनय की दुनिया में वे "शिवाजी गणेशन" के नाम से अमर हो गए।

बचपन से ही उनका रुझान अभिनय की ओर था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही घर छोड़ दिया और एक नाट्य मंडली से जुड़ गए। उस समय अभिनय को समाज में बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, फिर भी उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में रहकर अभिनय सीखा और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई। सीमित साधनों के बावजूद उनके भीतर सीखने की प्रबल इच्छा थी, जिसने उन्हें निरंतर आगे बढ़ाया।

उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने एक नाटक में महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाई। उनके प्रभावशाली अभिनय से प्रभावित होकर उन्हें "शिवाजी" की उपाधि दी गई, जो आगे चलकर उनके नाम का स्थायी हिस्सा बन गई। यह घटना बताती है कि सच्ची प्रतिभा कभी छुपी नहीं रहती और अवसर मिलने पर वह अवश्य चमकती है।

फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने 1952 में तमिल फिल्म "पराशक्ति" से की। इस फिल्म में उनके दमदार संवाद और गहरी भावनात्मक अभिव्यक्ति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक सफल फिल्मों में काम किया और हर किरदार को जीवंत बना दिया। चाहे ऐतिहासिक भूमिका हो, सामाजिक मुद्दों पर आधारित चरित्र हो या पारिवारिक कहानी—हर भूमिका में उन्होंने अपनी अदाकारी की अलग छाप छोड़ी। उनकी कला में सजीवता और सच्चाई झलकती थी।

उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी संवाद अदायगी और भावनाओं की गहराई थी। वे किसी भी किरदार को इतने प्रभावी ढंग से निभाते थे कि दर्शक उस चरित्र से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। यही कारण है कि उन्हें "नटसम्राट" यानी अभिनय का सम्राट कहा गया। उनकी आवाज, हाव-भाव और अभिव्यक्ति का समन्वय अद्वितीय था। शिवाजी गणेशन केवल एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि अनुशासन और मेहनत के प्रतीक भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे हमेशा सीखने और बेहतर बनने की कोशिश करते रहे। नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए वे प्रेरणा स्रोत बन गए और उन्होंने सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

उन्हें अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। यह सम्मान भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो उनके अद्वितीय योगदान को दर्शाता है। इसके अलावा उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो और कठिनाइयों से घबराए नहीं, तो वह किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। गरीबी, संघर्ष और समाज की बाधाओं के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को साकार किया।

21 जुलाई 2001 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी कला और प्रेरणा आज भी जीवित है। शिवाजी गणेशन का जीवन हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश है, जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है—मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।

हमारी गीता

महानुभाव

स्वामिनी निष्कलानंदा
चिन्मय मिशन कल्याण

अर्जुन के सरल मन में द्रोणाचार्य तथा भीष्माचार्य के प्रति बहुत आदर है। परंतु मन की आसक्ति के कारण दोष या तो दिखाई नहीं देते, या फिर दोष भी गुण लगने लगते हैं। अर्जुन कहता है— 'गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके।' अर्थात गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि हम इस लोक में भीख माँगकर जीवन यापन करें।

अर्जुन की दृष्टि से वे पूजनीय हैं, और उनके लिए वह स्वयं धर्म छोड़ने को तैयार हो रहा है। जबकि भीख माँगना धर्म नहीं है। संन्यासी होने पर भिक्षा पर रहना धर्म होता है, क्षत्रियों के लिए नहीं।

व्यक्तिगत दृष्टि से वे पूजनीय हो सकते हैं, परंतु युद्ध की दृष्टि से व्यक्तिगत मत का कोई स्थान नहीं है। व्यक्ति गुणवान, पराक्रमी और यशस्वी हो सकता है, परंतु यदि वह अधर्म का पक्ष लेता है तो वह शत्रु ही है। जो अधर्म का पक्ष ले रहे हैं, उन्हें महानुभाव कैसे कहा जा सकता है? वे अर्थकाम में लिप्त हैं, इसलिए महानुभाव नहीं हैं।

युद्ध से पूर्व युधिष्ठिर प्रणाम करने के लिए गए थे। तब दोनों ने आशीर्वाद दिया— "युधिष्ठिर, विजय तुम्हारी होगी।" तब युधिष्ठिर ने पूछा— "यदि विजय हमारी होगी, तो आप कौरवों की ओर से युद्ध क्यों कर रहे हैं?" तब उनका उत्तर था— "हमने कौरवों का नमक खाया है। कौरवों ने हमें बहुत धन-धान्य दिया है। हम विवश हैं, उनके अधीन हैं।" इस प्रकार वे अर्थ के वश में हैं, महानुभाव नहीं। अपनों के दोष दिखाई नहीं देते। विषाद के कारण विवेक-बुद्धि कार्य नहीं करती। विवेक को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। केवल भिक्षा माँगने से या घर छोड़कर हिमालय में जाने से कोई संन्यासी नहीं बन सकता।

इस प्रकार अर्जुन सम्मूढ़ हो गया है। वह अधर्म को भी धर्म समझ बैठा है। धर्म अर्थात कर्तव्य के साथ-साथ उसके फल के विषय में भी वह भ्रमित है। वह कहता है— "मुझे समझ नहीं आता कि जीतना और हारना, इनमें से क्या उचित है।" इस सम्मूढ़ता के कारण वह केवल युद्ध से ही नहीं भाग रहा, बल्कि जीवन से भी हार रहा है। वह संन्यास लेने की सोच रहा है।

जीवन ऊर्जा — जन्म

मैक्सिम गोर्की : जन्म : 28 मार्च 1868

श्रम ही सम्मान का आधार है

मैक्सिम गोर्की का जन्म 28 मार्च 1868 को रूस में हुआ था। उनका वास्तविक नाम अलेक्सी मक्सिमोविच पेशकोव था। वे रूसी साहित्य के महान लेखक और समाजवादी विचारक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में गरीबी, संघर्ष और मजदूरों के जीवन को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख कृतियां "मां" और "बाल्यकाल" हैं। उनका निधन 18 जून 1936 को हुआ।

मनुष्य महान कर्मों से बनता है। जीवन संघर्ष का नाम है। सत्य सबसे बड़ी शक्ति है। श्रम ही सम्मान का आधार है। डर इंसान को कमजोर बनाता है। साहस ही जीवन का मार्ग है। ज्ञान से ही प्रकाश मिलता है।

हर इंसान में क्षमता होती है। कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं। सपने देखो और उन्हें पूरा करो। आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन में गिरना भी जरूरी है। दूसरों के लिए जीना ही सच्चा जीवन है। आशा कभी मत छोड़ो। सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं।

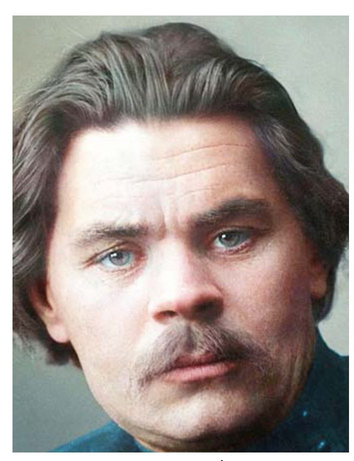

कर्म ही भाग्य बनाता है। विचार ही इंसान को महान बनाते हैं। संघर्ष से ही सफलता मिलती है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। सीखना कभी बंद मत करो। हर दिन नया अवसर है। दुख हमें सिखाता है। सफलता साहसी को मिलती है।

खुद पर विश्वास रखो। मेहनत से ही पहचान बनती है। जीवन एक अवसर है। असफलता अंत नहीं है। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए जिए। लक्ष्य पर ध्यान रखो। हार मानना सबसे बड़ी हार है। सकारात्मक सोच ही आगे बढ़ाती है। इंसान वही है जो अपने संघर्ष से इतिहास लिखता है।

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्यप्रदेश

प्रलोभन की परीक्षा और ईमानदारी का महत्व

मानव जीवन में ईमानदारी और लोभ के बीच संघर्ष बहुत पुराना है। प्रस्तुत कथा इसी सत्य को उजागर करती है कि जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं, जब हमारे सामने प्रलोभन खड़ा होता है और हमारी असली परीक्षा होती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है, जो प्रारंभ में ईमानदार दिखाई देता है, लेकिन अंततः लालच के कारण अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देता है।

कहानी के अनुसार, एक व्यक्ति काम की तलाश में भटकते हुए निराश होकर घर लौट रहा था। तभी एक बूढ़े ने उसे मजदूरी का प्रस्ताव दिया। बूढ़ा तीन गठरियाँ लेकर खड़ा था और उसे रामगढ़ तक पहुँचाने के लिए मजदूर की आवश्यकता थी। व्यक्ति ने सहर्ष यह काम स्वीकार कर लिया। पहली गठरी उठाते ही उसे उसके भारीपन का एहसास हुआ। बूढ़े ने बताया कि उसमें सिक्के हैं, लेकिन व्यक्ति ने उस समय ईमानदारी का परिचय देते हुए किसी भी प्रकार के लालच से खुद को दूर रखा।

पंडित कैलाशचंद्र शर्मा
वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक।
मो. नं. 9425980556

आगे चलते हुए नदी आई, जहाँ बूढ़े ने अपनी कमजोरी का हवाला देकर एक और गठरी उसे सौंप दी। इस बार भी व्यक्ति ने बिना किसी स्वार्थ के मदद की। वह खुद को ईमानदार और सिद्धांतों वाला मानता रहा। लेकिन जैसे-जैसे रास्ता कठिन होता गया, वैसे-वैसे उसकी परीक्षा भी कठिन होती गई।

जब पहाड़ी आई, तो बूढ़े ने तीसरी गठरी भी उसे सौंप दी और बताया कि उसमें सोने के सिक्के हैं। यहीं से उसके मन में लालच ने जन्म लिया। पहले वह खुद को ईमानदार समझता था, लेकिन अब उसके मन में विचार आने लगे कि यदि वह इन गठरियों को लेकर भाग जाए, तो उसका जीवन बदल सकता है। उसने सोचा कि धन से उसे सम्मान, सुख और आराम सब कुछ मिल सकता है।

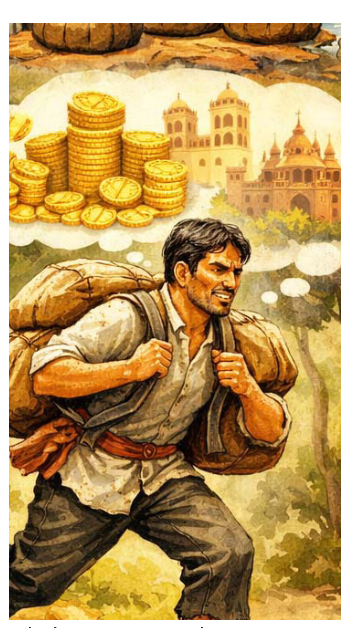

अंततः वह अपने लालच पर काबू नहीं रख सका और बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ। भारी गठरियों के साथ दौड़ते-दौड़ते वह किसी तरह घर पहुँचा और जब उसने गठरियाँ खोलीं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनमें असली सिक्कों की जगह मिट्टी के ढेले थे। उसकी सारी आशाएँ एक ही पल में टूट गईं। तभी उसे एक कागज मिला, जिसमें लिखा था कि यह सब एक परीक्षा थी। वह बूढ़ा वास्तव में राज्य का महाराजा था, जो एक ईमानदार सुरक्षामंत्री की खोज में था। यदि वह व्यक्ति ईमानदारी पर कायम रहता, तो उसे मंत्री पद और सम्मान दोनों मिलते। लेकिन उसने क्षणिक लालच में आकर अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दिया।

यह कथा हमें गहरा संदेश देती है कि जीवन में प्रलोभन क्षणिक होता है, लेकिन उसके परिणाम स्थायी होते हैं। ईमानदारी और सिद्धांतों पर टिके रहना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। हमें हमेशा सच और नैतिकता का साथ देना चाहिए, क्योंकि कौन जाने कब जीवन हमारी परीक्षा ले ले।

अतः यह आवश्यक है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्यों से समझौता न करें। लालच हमें क्षणिक लाभ दे सकता है, लेकिन अंततः वह हमें पछतावे के सिवा कुछ नहीं देता। सच्ची बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने चरित्र को मजबूत रखें और हर परीक्षा में ईमानदारी से उत्तीर्ण हों।

अपने विचार

जनता ने बालेन के नेतृत्व पर जो भरोसा जताया है,वह सराहनीय है और भारत-नेपाल संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए वह उनके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं. यह बयान केवल औपचारिक नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी की दिशा में एक मजबूत संकेत है।

-नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री ,भारत

लॉकडाउन को लेकर जो भी बातें कही जा रही हैं वे पूरी तरह निराधार हैं. उन्होंने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार हालात पर नजर रखे हुए है, लेकिन फिलहाल देश में किसी भी तरह के लॉकडाउन की योजना नहीं है!

-हरदीप सिंह पुरी
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री

दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और सेवा का दावा करनेवाले भाजपाई और उनके संगी-साथी अब कहां नदारद हैं?गैस और तेल की लाइन में लगे लोगों को समझाने और सिलेंडर व तेल दिलवाने के लिए वो गले में भाजपा का पट्टा और गाड़ियों पर भाजपा का झंडा लगाकर क्यों नहीं निकल रहे हैं?

-अखिलेश यादव अध्यक्ष,
समाजवादी पार्टी

यह गठबंधन आने वाले केरल विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाएगा।कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) जीत के लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि केरल की जनता पिनाराई विजयन के नेतृत्व में एक दशक बिताने के बाद अब सरकार में बदलाव चाहती है।

-केसी वेणुगोपाल
महासचिव, AICC

अपने विचार
डीबीडी कार्यालय
ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के.के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई-400001
indiagroundreport@gmail.com
भेज सकते हैं।

यह अखबार "माध्यम कार्पोरेट सर्विसेज लि. " के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक अरुण लाल द्वारा ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के. के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 से प्रकाशित एवं सोमानी प्रिंटिग प्रेस, गाला नं. 4, एन.के.इंडस्ट्रियल इस्टेट, इनसाइड प्रवासी इंडिस्ट्रयल इस्टेट गेट नं. 2, गोरेगांव पू., मुंबई-63 से मुद्रित. फोन नं. 022-66555719 ईमेल : indiagroundreport@gmail.com कार्यकारी संपादक : अमित बृज (पी.आर.बी. अधिनियम के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए ज्मिेदार).

ब्रीफ न्यूज़

अवैध प्रतिमा हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की चेतावनी

उल्हासनगर। सामाजिक कार्यकर्ता राज असरोंडकर ने शांतिनगर (कैंप-3) स्थित श्मशान भूमि से डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की अवैध प्रतिमा को सम्मानपूर्वक हटाने की मांग को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने गृह सचिव मनीषा म्हैस्कर को ईमेल भेजकर चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे 1 अप्रैल से अपने आवास पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। असरोंडकर पिछले छह महीनों से इस मुद्दे पर प्रशासन से पत्राचार कर रहे हैं और उनका कहना है कि कब्रिस्तान में प्रतिमा स्थापित करना 2017 की प्रतिमा नीति का उल्लंघन है, साथ ही इसके लिए जिला कलेक्टर की अनुमति भी नहीं ली गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिमा के आधारशिला पर मनपा का नाम होने के बावजूद प्रशासन जिम्मेदारी से बच रहा है और शिवसेना सांसद एकनाथ शिंदे का नाम जुड़े होने के कारण राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं, शिवसेना प्रवक्ता किरण सोनावाने ने स्पष्ट किया कि सांसद श्रीकांत शिंदे प्रतिमा के स्थानांतरण के विरोध में नहीं हैं और प्रक्रिया जारी है, जबकि महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी ने भी कहा कि जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित स्थान पर स्थानांतरण होने पर पार्टी मनपा का समर्थन करेगी।

सूरत स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित

सूरत। सूरत स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 2, 3 और 4 के बीच थ्रू रूफ लॉन्चिंग के पुनर्विकास कार्य के कारण 30 मार्च से 28 अप्रैल 2026 तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, इस 30 दिवसीय कार्य के चलते ट्रेन संख्या 12935 (बांद्रा टर्मिनस-सूरत) और ट्रेन संख्या 20926 (अमरावती-सूरत) सूरत के बजाय उधना स्टेशन पर ही अपनी यात्रा समाप्त करेंगी। इसके अतिरिक्त, ट्रेन संख्या 20925 (सूरत-अमरावती) सूरत के स्थान पर उधना स्टेशन से अपनी यात्रा प्रारंभ करेगी, जिससे ये ट्रेनें सूरत और उधना के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेंगी।

अब घर के पास मिलेगा वर्ल्ड क्लास इलाज

सीएम फडणवीस ने किया PULSE 2026 का उद्घाटन

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

बीकेसी में आयोजित 'पल्स 2026' सम्मेलन महाराष्ट्र के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मंच से न केवल आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया, बल्कि 'विकसित महाराष्ट्र 2047' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक के दरवाजे तक पहुँचाने का संकल्प भी दोहराया। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि 'पल्स' (Platform for Unified Learning, Skills, Health and Education) केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि अगले 10 सालों के लिए महाराष्ट्र की स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा तय करने वाला मंच है। सरकार का लक्ष्य तीन स्तंभों पर टिका है: गुणवत्ता, निरंतरता और सामर्थ्य।

कैंसर के खिलाफ त्रि-स्तरीय जंग

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रभावी इलाज के लिए महाराष्ट्र सरकार 'महाकेअर' मॉडल लागू कर रही है, जिसे तीन स्तरों में विभाजित किया गया है—जिला स्तर पर शुरुआती जांच और बीमारी की पहचान (डायग्नोसिस) की जाएगी, क्षेत्रीय स्तर पर सर्जरी और बुनियादी उपचार उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि उच्च केंद्रों (एडवांस्ड सेंटर्स) पर जटिल सर्जरी और आधुनिक रेडिएशन थेरेपी जैसी उन्नत सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि मरीजों को चरणबद्ध और बेहतर इलाज मिल सके।

स्वास्थ्य सेवा आपके द्वार

आम आदमी के लिए सबसे बड़ी घोषणा यह है कि राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को उनके घर से 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में सस्ती और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे ग्रामीण और दुर्गम इलाकों के लोगों को बड़े शहरों की ओर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

एआई और टेलीमेडिसिन का जादू

महाराष्ट्र अब स्वास्थ्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करने वाला अग्रणी राज्य बन रहा है। टीबी (क्षय रोग) के नियंत्रण और गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं की देखभाल के लिए एआई तकनीक का उपयोग होगा। साथ ही, ई-संजीवनी के माध्यम से गांव का मरीज घर बैठे शहर के विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह ले सकेगा। नागपुर में 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ' की स्थापना का प्रस्ताव है, जो स्वास्थ्य अनुसंधान (Research) को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री का विजन है कि महाराष्ट्र को 'मेडिकल वेलनेस टूरिज्म' का वैश्विक केंद्र बनाया जाए, जहाँ दुनिया भर से लोग इलाज के लिए आएं। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश और नौकरियों का भी बड़ा जरिया बनेगा।

अभय योजना को मिला भारी प्रतिसाद

डीबीडी संवाददाता । नवी मुंबई

नवी मुंबई नगर निगम द्वारा संपत्ति कर बकायेदारों के लिए लागू की गई 'अभय योजना' को नागरिकों का शानदार समर्थन मिल रहा है। अब तक 15 हजार से अधिक बकायेदारों ने 81 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया कर जमा किया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अब केवल चार दिन शेष बचे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 की मध्यरात्रि तक है। प्रशासन ने नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, 27 मार्च 2026 की शाम 5 बजे तक चालू वित्त वर्ष में कुल 755 करोड़ रुपये का संपत्ति कर जमा हो चुका है। अब तक 2 लाख 14 हजार 900 संपत्ति मालिकों ने अपना टैक्स भरा है। विशेष बात यह है कि इसमें 61.5% नागरिकों ने ऑनलाइन माध्यम से, जबकि 38.5% ने ऑफलाइन तरीके से भुगतान किया है। अभय योजना के तहत अब तक 15,092 बकायेदारों ने 81 करोड़ 34 लाख रुपये जमा कर दंड शुल्क में छूट का लाभ लिया है। इस योजना के अंतर्गत आवासीय, गैर-आवासीय, औद्योगिक और खाली भूखंडों के बकाया कर को एकमुश्त भरने पर विलंब शुल्क (Penalty) में 50% की रियायत दी जा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के समाप्त होने में केवल कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए नगर निगम ने कर वसूली अभियान को और तेज कर दिया है। आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे ने स्पष्ट किया है कि यह बकायेदारों के लिए अपनी देनदारियां कम करने का एक सुनहरा मौका है।

▶▶ 15 हजार से अधिक बकायेदारों ने भरे 81 करोड़ रुपये

4.68 लाख घरों की छतों पर चमका सूरज

समय से पहले हासिल किया अंतरिम लक्ष्य; 1.78 गीगावाट बिजली उत्पादन शुरू

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

केंद्र सरकार की पहल के साथ तालमेल बिठाते हुए महाराष्ट्र सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। महावितरण ने वर्ष 2026-27 तक 8.75 लाख घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने का लक्ष्य रखा है। मार्च 2026 तक 4.25 लाख घरों का अंतरिम लक्ष्य था, लेकिन समय से पहले ही 4.68 लाख उपभोक्ता इस योजना से जुड़ चुके हैं। इससे राज्य में कुल 1.78 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित हो चुकी है।

हाउसिंग सोसायटियों में बढ़ा सौर ऊर्जा का रुझान

सौर ऊर्जा को लेकर हाउसिंग सोसायटियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 4,472 सोसायटियों ने सामूहिक सौर परियोजनाएं अपनाई हैं, जिससे 74 मेगावाट बिजली क्षमता विकसित हुई है। इनमें से 4,053 सोसायटियों को 123.54 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है। मुंबई और उपनगरों की 58 सोसायटियां भी इस पहल में शामिल हैं।

एसआरए परियोजनाओं में भी तेजी

मुलुंड और भांडुप क्षेत्रों में महावितरण के करीब 3.10 लाख उपभोक्ता हैं, जहां 14 झोपड़पट्टी पुनर्वसन (SRA) परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इनमें से 11 परियोजनाओं ने सोलर कनेक्शन लेकर लाभ उठाया है। खास बात यह है कि फिलहाल इस योजना से जुड़ा कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।

बिजली बिल में राहत और सतत विकास पर जोर

सरकार का मानना है कि सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से एसआरए इमारतों के रखरखाव और बिजली बिल के खर्च में कमी आएगी। साथ ही यह पहल राज्य को स्वच्छ और सतत ऊर्जा की दिशा में मजबूत बनाएगी।

नई हाउसिंग पॉलिसी में सौर ऊर्जा को प्राथमिकता

राज्य सरकार ने 23 जुलाई 2025 को लागू नई हाउसिंग पॉलिसी में पर्यावरण-अनुकूल उपायों को प्राथमिकता दी है। इस नीति में सौर ऊर्जा को विशेष महत्व दिया गया है, ताकि शहरी विकास के साथ पर्यावरण संतुलन भी बना रहे।

जिला मेधावी शिक्षक पुरस्कार का नाम 'अजितदादा पवार' के नाम पर रखने की मांग

डीबीडी संवाददाता । पुणे

पुणे जिला प्राथमिक शिक्षक समिति ने मांग की है कि वर्ष 2025-26 के लिए 'मेधावी शिक्षक सम्मान' और 'आइडियल टीचर' समारोह तत्काल आयोजित किया जाए। समिति ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखते हुए मांग की है कि इस वर्ष से इन शिक्षकों को 'श्रद्धेय अजितदादा पवार मेधावी शिक्षक पुरस्कार' के नाम से सम्मानित किया जाए। यह मांग पुणे जिला परिषद के नवनियुक्त पदाधिकारियों के स्वागत समारोह के दौरान प्रमुखता से उठाई गई।

नवनियुक्त अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का भव्य सत्कार

पुणे जिला परिषद में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में, जिला प्राथमिक शिक्षक समिति की ओर से नवनियुक्त अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे और उपाध्यक्ष विवेक वलसे पाटिल का भावभीना सम्मान किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समिति के कोषाध्यक्ष नंदकुमार होलकर, राज्य सलाहकार महादेव मालवदकर पाटिल और पुणे शिक्षक समिति के अध्यक्ष सुनील वाघ सहित बड़ी संख्या में जिला और तालुका स्तर के पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने नए नेतृत्व का स्वागत करते हुए शिक्षा क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जताई। समारोह के पश्चात शिक्षक समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गजानन पाटिल और शिक्षा अधिकारी संजय नाइकडे से मुलाकात की। इस बैठक में शिक्षकों की लंबित मांगों और विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

ऑनलाइन तबादले और गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति की मांग

समिति ने प्रशासन के समक्ष कई प्रमुख मांगें रखीं, जिनमें इस वर्ष की ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया को तुरंत शुरू करना, विस्थापित और दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत महिला शिक्षकों को प्राथमिकता देना और लंबित मेडिकल बिलों का तत्काल निपटारा करना शामिल है। इसके अलावा, शिक्षकों को बी.एल.ओ. (BLO) और अन्य गैर-शैक्षणिक ऑनलाइन कार्यों से मुक्त करने की पुरजोर मांग की गई। समिति ने यह भी चेतावनी दी कि जो कर्मचारी भुगतान और फाइलों के निपटारे में लापरवाही बरत रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

अब 31 मार्च तक भरें आरटीई का फॉर्म

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

ठाणे और पूरे महाराष्ट्र के उन अभिभावकों के लिए राहत की खबर है जो अपने बच्चों का एडमिशन RTE (शिक्षा का अधिकार) के तहत कराना चाहते हैं। निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा अब बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है।पहले आवेदन की समय सीमा समाप्त हो रही थी, लेकिन अब अभिभावकों को 31 मार्च 2026 तक का अतिरिक्त समय दिया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कोई भी पात्र बच्चा तकनीकी कारणों या जानकारी के अभाव में शिक्षा के इस अधिकार से वंचित न रह जाए।

1 किमी की शर्त खत्म

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव स्कूल और घर की दूरी को लेकर है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के निर्देशानुसार, अब 1 किमी के दायरे की अनिवार्य शर्त को हटा दिया गया है। अब अभिभावक 3 से 5 किमी की दूरी के भीतर स्थित स्कूलों को भी अपने आवेदन में चुन सकते हैं। इससे बच्चों के पास बेहतर स्कूल चुनने के विकल्प बढ़ गए हैं। जिन अभिभावकों ने पहले ही फॉर्म भर दिया है लेकिन उनसे कोई गलती हो गई है, उनके लिए पोर्टल पर 'अनकन्फर्मिंग' और 'कन्फर्मिंग' का विकल्प दिया गया है। इसके जरिए आप अपने आवेदन को फिर से खोलकर उसमें ज़रूरी सुधार कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल पर विशेष पॉप-अप नोटिफिकेशन की व्यवस्था की है। जैसे ही अभिभावक वेबसाइट खोलेंगे, उन्हें समय सीमा बढ़ने और सुधार की प्रक्रिया के बारे में सीधा संदेश दिखाई देगा, ताकि वे किसी भी अपडेट से चूक न जाएं।

शिक्षा अधिकारी की अपील

ठाणे जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षा अधिकारी बालासाहेब राक्षे ने सभी पात्र अभिभावकों से अपील की है कि वे इस बढ़ी हुई समय सीमा का पूरा लाभ उठाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करें और इस जानकारी को अन्य ज़रूरतमंद परिवारों तक भी पहुँचाएं।

कांदिवली-बोरीवली के बीच जम्बो ब्लॉक

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

पश्चिम रेलवे द्वारा ब्रिज संख्या 61 के री-गर्डरिंग कार्य के चलते कांदिवली और बोरीवली स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन स्लो लाइनों पर 28 मार्च 2026 की रात 22:30 बजे से 29 मार्च 2026 को 19:30 बजे तक जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा। इसके अलावा 29 मार्च को डाउन फास्ट लाइन पर भी 01:00 बजे से 04:30 बजे तक ब्लॉक रहेगा।

यात्रियों पर असर, कई सेवाएं प्रभावित

ब्लॉक अवधि के दौरान बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर कोई ट्रेन नहीं चलेगी। कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी, जबकि कुछ को अंधेरी और गोरेगांव तक सीमित किया जाएगा। साथ ही, 15-डिब्बों वाली सभी स्लो सेवाएं अंधेरी और बोरीवली के बीच फास्ट ट्रेन के रूप में चलाई जाएंगी।

ट्रेनों के संचालन में बदलाव

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, स्लो लाइन ब्लॉक के दौरान सभी स्लो ट्रेनें गोरेगांव और बोरीवली के बीच फास्ट लाइन पर चलाई जाएंगी। वहीं, डाउन फास्ट लाइन ब्लॉक के दौरान प्लेटफॉर्म उपलब्ध न होने के कारण ट्रेनें 5वीं लाइन से संचालित होंगी और राम मंदिर, मालाड तथा कांदिवली स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी।

पश्चिम रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्पेशल ट्रेनों के फेरों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

मुंबई-काठगोदाम और कानपुर रूट को राहत

ट्रेन संख्या 09075/09076 मुंबई सेंट्रल-काठगोदाम स्पेशल को क्रमश: 29 और 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाया गया है। वहीं 09185/09186 मुंबई सेंट्रल-कानपुर अनवरगंज स्पेशल को 26 और 27 जुलाई 2026 तक विस्तारित किया गया है।

बांद्रा-भिवानी और वलसाड-दानापुर सेवाएं जारी

ट्रेन संख्या 09005/09006 बांद्रा टर्मिनस-भिवानी स्पेशल को 29 और 30 जुलाई 2026 तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा 09025/09026 वलसाड-दानापुर स्पेशल को 29 और 30 जून 2026 तक विस्तार मिला है।

अनारक्षित और पूर्वांचल रूट्स को भी लाभ

उधना-हसनपुर रोड अनारक्षित स्पेशल (09031/09032) को 28 और 29 जून 2026 तक बढ़ाया गया है। वहीं सूरत-छपरा स्पेशल (09065/09066) को 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

अहमदाबाद, हरिद्वार और पटना रूट भी शामिल

अहमदाबाद-पटना (09447/09448) स्पेशल को 29 अप्रैल और 1 मई 2026 तक बढ़ाया गया है।

12 राशिफल में देखें अपना दिन

प्रियंका जैन
97699 94439

मेष प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। भेंट व उपहार देना पड़ सकते हैं। बेवजह तनाव रह सकता है। सिर में चोट लग सकती है। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। घर में अतिथियों का आगमन होगा। व्यय बढ़ेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

वृष मित्रों तथा पारिवारिक सदस्यों के साथ समय सुखमय व्यतीत होगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। प्रमाद न करें। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे।

मिथुन कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आएगा। कर्ज लेना पड़ सकता है। असमंजस की स्थिति बनेगी। लेन-देन में जल्दबाजी व लापरवाही न करें। भावनाओं को वश में रखें। मन की बात किसी को न बतलाएं। प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है।

कर्क यात्रा लंबी तथा मनोरंजक रह सकती है। अप्रत्याशित लाभ के योग हैं। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। जीवन सुखमय व्यतीत होगा। प्रसन्नता तथा उत्साह से ओत-प्रोत रहेंगे। पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा।

सिंह ऐश्वर्यादि पर खर्च होगा। यश बढ़ेगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। नए काम मिल सकते हैं। आर्थिक वृद्धि के लिए योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। कारोबार में वृद्धि के योग हैं। नौकरी में जवाबदारी बढ़ सकती है। थकान व कमजोरी रह सकती है।

कन्या सुख के साधन जुटेंगे। यात्रा मनोरंजक रहेगी। मित्रों का साथ मिलेगा। प्रयास सफल रहेंगे। किसी विवाद में विजय मिल सकती है। सामाजिक काम करने का मन बनेगा। पराक्रम व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। कारोबारी कामकाज चलते रहेंगे।

तुला वाहन व मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही न करें। अनहोनी की आशंका निर्मूल नहीं हो सकती है। पुराना रोग उभर सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। दूसरों के मामलों में हाथ न डालें। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। किसी व्यक्ति के व्यवहार से क्लेश होगा।

वृश्चिक शारीरिक कष्ट संभव है। चिंता तथा तनाव रहेंगे। संतान संबंधी बुरी सूचना प्राप्त हो सकती है। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। सृजनशीलता का विकास होगा। धन प्राप्ति सुगम होगी।

धनु प्रियजनों के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है। विवाद को बढ़ावा न दें। दूर से दु:खद समाचार मिल सकता है। पुराने रोग को नजरअंदाज न करें। व्यय होगा। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। व्यापार-व्यवसाय की गति धीमी रहेगी।

मकर विवेक से कार्य करें, लाभ होगा। किसी धार्मिक स्थल के दर्शन का कार्यक्रम बन सकता है। मित्रों से भेंट होगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त होगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। जीवनसाथी की चिंता रहेगी।

कुंभ स्थायी संपत्ति की खरीदी-बिक्री की योजना बनेगी। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। पार्टनरों तथा मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के उकसाने में न आएं।

मीन परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी चिंता रहेगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। शत्रुभय रहेगा। नौकरी में मातहतों का सहयोग मिलेगा।

हनुमानजी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है: भक्ति, प्रेम और समर्पण की अद्भुत कथा

प्रियंका जैन
97699 94439

जब भगवान श्रीराम ने लंका विजय के बाद अयोध्या में राज्य संभाला, तब चारों ओर शांति और धर्म की स्थापना हो चुकी थी। रावण का अंत हो चुका था और अयोध्या फिर से मर्यादा, प्रेम और धर्म का केंद्र बन गई थी। इसी पावन वातावरण में एक ऐसी घटना घटी, जिसने सदियों से चली आ रही एक महान परंपरा को जन्म दिया—हनुमानजी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा। हनुमान, जो केवल एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि भक्ति की सर्वोच्च मिसाल हैं, अयोध्या में ही रह गए थे। उनका जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए समर्पित था—प्रभु श्रीराम की सेवा और उनके चरणों में रहना। एक दिन जब श्रीराम अपने परिवार के साथ निजी कक्ष में थे, तब भी हनुमान उनके पास ही बैठे रहे। उस समय माता सीता भी वहाँ उपस्थित थीं। परिवार के अन्य सदस्यों को लगा कि अब श्रीराम और सीता को एकांत मिलना चाहिए, इसलिए हनुमान को संकेतों में बाहर जाने को कहा गया। लेकिन हनुमान, जो अपने प्रभु से एक क्षण भी दूर रहना नहीं चाहते थे, उन संकेतों को समझ नहीं पाए या शायद समझकर भी अनदेखा कर गए। जब उनसे स्पष्ट रूप से कहा गया कि श्रीराम को एकांत चाहिए, तब उन्होंने एक मासूम प्रश्न पूछा—"माता सीता क्यों रह सकती हैं और मैं क्यों नहीं?" इस पर उत्तर मिला कि माता सीता के माथे पर लगा सिंदूर उनके उस अधिकार का प्रतीक है, जो उन्हें श्रीराम के साथ हर समय रहने का अधिकार देता है। यह सुनकर हनुमान के मन में एक अद्भुत विचार आया। उन्होंने सोचा कि यदि एक चुटकी सिंदूर लगाने से श्रीराम के निकट रहने का अधिकार मिलता है, तो क्यों न वे अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लें, ताकि वे सदा-सर्वदा अपने प्रभु के सबसे निकट रह सकें। अगले ही दिन जब राजदरबार सजा, तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान पूरे शरीर पर सिंदूर लगाए, प्रसन्न मुद्रा में दरबार में उपस्थित हुए। उनके शरीर से सिंदूर झर रहा था और वे अत्यंत आनंदित दिखाई दे रहे थे। जब उनसे इसका कारण पूछा गया, तो उन्होंने बड़ी सरलता से कहा—"मुझे पता चला कि सिंदूर लगाने से प्रभु श्रीराम प्रसन्न होते हैं और उनके निकट रहने का अधिकार मिलता है, इसलिए मैंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, ताकि मैं हमेशा उनके पास रह सकूँ।" उनकी यह बालसुलभ, निष्कपट और समर्पित भक्ति देखकर पूरा दरबार भाव-विभोर हो गया। भरत जैसे महान भक्त भी भावुक होकर रो पड़े। उन्होंने कहा कि ऐसा समर्पण, ऐसा प्रेम और ऐसी भक्ति संसार में दुर्लभ है। एक महान ज्ञानी, बलशाली और सिद्धियों के स्वामी होकर भी हनुमान ने अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया और केवल अपने प्रभु के प्रेम में लीन हो गए। इस कथा का एक दूसरा प्रसंग भी अत्यंत प्रसिद्ध है। एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थीं। हनुमान ने जिज्ञासावश पूछा कि यह क्या है और इसे लगाने का क्या महत्व है। तब माता सीता ने बताया कि सिंदूर लगाने से श्रीराम की आयु लंबी होती है और वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। यह सुनकर हनुमान के मन में एक और भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि जब थोड़े से सिंदूर से प्रभु की आयु बढ़ सकती है, तो यदि वे अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लें, तो श्रीराम अजर-अमर हो जाएंगे। बस, फिर क्या था—उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से ढक लिया और उसी अवस्था में दरबार में पहुंच गए। जब श्रीराम ने यह देखा, तो वे मुस्कुराए और हनुमान से इसका कारण पूछा। हनुमान ने अत्यंत सरलता से अपनी भावना प्रकट की। उनकी यह निष्कपट भक्ति देखकर श्रीराम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सदा अमर रहेंगे और युगों-युगों तक उनकी भक्ति का गुणगान किया जाएगा।

न्यूज़ ब्रीफ

चुनावी तैयारियों के बीच तबादलों पर आयोग की रोक

शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर अस्थायी रोक लगा दी है। इस संबंध में मुख्य सचिव को निर्देश जारी करते हुए सभी विभागों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। आयोग का मानना है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान संबंधित कर्मियों की निरंतर उपलब्धता जरूरी है, ताकि निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 31 मई 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी की जानी है।

करंट से मादा भालू और दो शावकों की मौत

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कटघोरा वनमंडल अंतर्गत केंदई वन परिक्षेत्र में बिजली तार की चपेट में आने से एक मादा भालू और उसके दो शावकों की मौत हो गई। घटना की जानकारी उस समय मिली जब मोरगा-सरईगोट क्षेत्र में जंगल गए ग्रामीणों ने तीनों वन्यजीवों को मृत अवस्था में देखा और वन विभाग को सूचित किया। मौके पर पहुंची टीम ने जांच में पुष्टि की कि मृत भालू एक ही परिवार के थे और करंट लगने से उनकी जान गई। प्राथमिक जांच में विद्युत लाइन बिछाने में लापरवाही सामने आने के बाद संबंधित लाइनमैन को हिरासत में लिया गया है। वनमंडल अधिकारी कुमार निशांत ने बताया कि विद्युत लाइन का कार्य बिना वन विभाग को सूचित किए किया गया।

वरिष्ठ आईपीएस रतन लाल डांगी निलंबित

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में उनके आचरण को सेवा नियमों के प्रतिकूल और पद की गरिमा के विपरीत बताया गया है। प्रारंभिक जांच में उन पर अशोभनीय व्यवहार, पद के दुरुपयोग और नैतिक मानकों के उल्लंघन के आरोप सही पाए गए हैं, जिससे पुलिस विभाग की छवि प्रभावित होने की बात भी सामने आई है। सरकार ने मामले को गंभीर मानते हुए अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के तहत कार्रवाई की है और उनके खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है।

बर्ड फ्लू सख्ती: अंडा-चिकन बिक्री पर रोक

- शासकीय पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि
- प्रशासन ने दस किलोमीटर के एरिया में लगाई पाबंदी

एजेंसी । बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं। कोनी स्थित शासकीय पोल्ट्री फार्म में संक्रमण की पुष्टि के बाद प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर दायरे में चिकन और अंडों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर नगर निगम, पशुपालन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी में जुटी हैं। पोल्ट्री फार्म, चिकन दुकानों, होटल और रेस्टोरेंट्स में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। नियमों के उल्लंघन पर सामग्री जब्त कर नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रतिबंधित क्षेत्र में निगरानी के लिए नौ विशेष टीमें गठित की गई हैं।

निगरानी के लिए नौ टीमें गठित

जो शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार भ्रमण कर रही हैं। संक्रमण के मद्देनजर सेंदरी, मोपका, तोरवा, लालखदान, राजकिशोर नगर, तिफरा, सकरी, उसलापुर और तारबाहर सहित कई इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संक्रमित क्षेत्र के एक किलोमीटर दायरे में पूरी तरह कड़ी पाबंदी लागू है और बाहर से चिकन या अंडे लाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। पोल्ट्री फार्म में साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। यह प्रक्रिया करीब एक सप्ताह तक चलने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय है और प्रभावित क्षेत्र में घर-घर सर्वे कराया जा रहा है। अब तक कुछ लोगों में सामान्य सर्दी-जुकाम के लक्षण मिले हैं।

रोजाना 50 लाख का कारोबार ठप

इस फैसले का असर कारोबार पर भी पड़ा है। प्रभावित क्षेत्र में रोजाना होने वाला करीब 50 लाख रुपये का चिकन और अंडा कारोबार ठप हो गया है। कई नॉनवेज रेस्टोरेंट्स ने एहतियातन अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं, जबकि अन्य स्थानों पर इन उत्पादों की उपलब्धता रोक दी गई है। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि स्थिति सामान्य होने तक सावधानी बरतें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। हालांकि स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। लोगों को बीमार पक्षियों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पशुपालन विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. जीएसएस. तंवर ने बताया कि संक्रमित क्षेत्र के साथ ही आसपास के 10 किमी के दायरे में किसी भी प्रकार की चिकन और अंडे की खरीद-बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।

संभल कब्रिस्तान विवाद: यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश

- हाईकोर्ट ने प्रशासन की बेदखली नोटिस पर लगाई रोक

एजेंसी । प्रयागराज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल स्थित शाही जामा मस्जिद से जुड़े कब्रिस्तान की भूमि को लेकर जारी बेदखली नोटिस पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने अली अशरफ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत ने एक जनवरी 2026 को संभल जिला प्रशासन द्वारा जारी नोटिस की वैधता पर प्रश्न उठाते हुए उस पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी और शशांक श्रीत्रिपाठी ने दलील दी कि प्रशासन ने बिना स्पष्ट कानूनी प्रावधान का उल्लेख किए जल्दबाजी में नोटिस जारी किया।

दिसंबर में दिया था पैमाइश का निर्देश

पक्षकारों ने यह भी बताया कि इसी विवाद को लेकर 31 दिसंबर 2025 को दाखिल एक अन्य मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सभी संबंधित पक्षों की उपस्थिति में स्थल की पैमाइश कर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद प्रशासन ने अगले ही दिन नोटिस जारी कर दिया, जो न्यायालय के पूर्व आदेश की अवहेलना है। अदालत ने प्रथम दृष्टया प्रशासन की कार्रवाई को प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण मानते हुए नोटिस पर रोक लगाई और मामले की अगली सुनवाई के लिए छह मई की तिथि निर्धारित की है।

अनुसूचित जाति के लिए बनेंगे अत्याधुनिक छात्रावास

- जौनपुर, सुल्तानपुर, हाथरस और फिरोजाबाद में होगा निर्माण
- छह अत्याधुनिक छात्रावासों के लिए 12.30 करोड़ रुपये की मंजूरी

एजेंसी । लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक माहौल और आधुनिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में छह नए छात्रावासों के निर्माण का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से यह परियोजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। सरकार का मानना है कि यह पहल सामाजिक समावेशन को मजबूत करने के साथ शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करेगी।

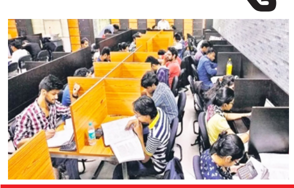

लर्निंग सेंटर के रूप में होगा विकास

योजना के अंतर्गत जौनपुर, सुल्तानपुर और हाथरस में एक-एक छात्रावास तथा फिरोजाबाद में तीन छात्रावासों का निर्माण प्रस्तावित है। इन सभी को आधुनिक सुविधाओं से युक्त परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आवास मिल सके।

हास्टल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान

समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि निर्माण कार्य में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए धनराशि का संचालन एसएनए (स्पर्श) खाते के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी विकास पर जोर दे रही है।

उत्पाद शुल्क में कटौती से आम जनता को राहत: पंकज चौधरी

- केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में की कटौती

एजेंसी । लखनऊ

केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में की गई कटौती को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम आम जनता को महंगाई से राहत देने वाला है।

पेट्रोल पर दस रुपये की कटौती

वहीं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस निर्णय को आम लोगों के लिए राहतभरा बताया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये की कटौती कर इसे 3 रुपये किया गया है।

चाचा ने तीन मासूमों का गला रेता

एजेंसी । औरंगाबाद

बिहार के औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र स्थित खुटहन गांव में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की निर्ममता से हत्या कर दी। मृतकों में 10 वर्षीय अनीश कुमार, 7 वर्षीय आयुष कुमार और 5 वर्षीय अनुष्का कुमारी शामिल हैं, जो एक ही परिवार के भाई-बहन थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोपी चाचा सुबह घर लौटा और भीतर प्रवेश करने के बाद तेज आवाज में स्पीकर चला दिया।

हिमकेयर योजना पर विधानसभा में तीखी तकरार

- पेट्रोल पर दस रुपये घटाकर तीन रुपये किया टैक्स
- आंतरिक आडिट में 100 करोड़ की गड़बड़ी के संकेत

एजेंसी । शिमला

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हिमकेयर योजना को लेकर शुक्रवार को सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव देखने को मिला। प्रश्नकाल के बाद उठे इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आमने-सामने आ गए।

जांच अभी प्रारंभिक चरण में

विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, तो इतनी बड़ी गड़बड़ी का दावा करना उचित नहीं है।

योजना को बनाएंगे पारदर्शी: सुक्खू

इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य हिमकेयर योजना को समाप्त करना नहीं है, बल्कि उसमें पाई गई कमियों को दूर कर उसे अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर नई स्वास्थ्य योजना पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता अनियमितताओं की जांच और सुधारात्मक कदम उठाने की है। सदन में इस मुद्दे पर जारी बहस से साफ है कि आने वाले दिनों में यह मामला और अधिक राजनीतिक तूल पकड़ सकता है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए। ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार इस योजना को बदनाम कर इसे बंद करने की कोशिश कर रही है। जिससे सदन में आरोप-प्रत्यारोप का माहौल बन गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर तीखे सवाल उठाए और योजना की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त कीं।

हार्डकोर नक्सली स्वरूपा का भावुक पत्र वायरल, साथियों से की अपील

रक्तपात छोड़ मुख्यधारा में लौटें

एजेंसी । कांकेर

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाली 8 लाख रुपये की इनामी महिला नक्सली स्वरूपा का एक हस्तलिखित पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिलिट्री कंपनी नंबर-5 से जुड़ी रही स्वरूपा ने यह पत्र गोंडी भाषा में लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने पूर्व साथियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन अपनाने की अपील की है।

समाज से जुड़ना ही बेहतर विकल्प

पत्र में स्वरूपा ने स्पष्ट किया है कि जंगल और हथियारों का रास्ता अंततः विनाश की ओर ले जाता है। उन्होंने अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि समय रहते आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटना ही बेहतर विकल्प है। यह पत्र परतापुर एरिया कमेटी के कमांडर चंदर रूपी के नाम लिखा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि वह सीधे सक्रिय नक्सली सदस्यों तक

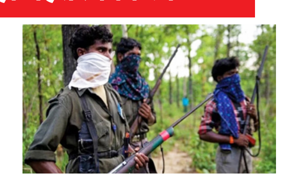

अपना संदेश पहुंचाना चाहती हैं। आठ लाख की इनामी थी नक्सली स्वरूपा उल्लेखनीय है कि आठ लाख रुपये की इनामी स्वरूपा ने गुरुवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर नक्सलवाद से दूरी बना ली थी।

व्यापार जगत

राहत: पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती

- पेट्रोल पर दस रुपये घटाकर तीन रुपये कि टैक्स
- डीजल पर पूरी तरह से खत्म किया उत्पाद शुल्क

एजेंसी । नई दिल्ली

वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बीच केंद्र सरकार ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती की है। सरकार ने पेट्रोल पर यह शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, जबकि डीजल पर इसे 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

घरेलू बाजार पर लगातार बढ़ रहा बोझ

सरकार के इस फैसले को महंगाई के दबाव को कम करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण घरेलू बाजार पर बढ़ते बोझ को देखते हुए यह राहत दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से परिवहन लागत में कमी आएगी, जिसका असर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है।

महंगाई पर राहत

पेट्रोल-डीजल पर शुल्क में कटौती से आम उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। ईंधन सस्ता होने से परिवहन लागत घटेगी, जिससे खाद्य वस्तुओं, रोजमर्रा के सामान और लॉजिस्टिक्स खर्च पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। इससे महंगाई दर को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही उद्योगों, खासकर परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी राहत मिलने की संभावना है।

सरकार की चुनौतियां

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं, जिससे आने वाले दिनों में ईंधन कीमतों में कमी की संभावना जताई जा रही है। उत्पाद शुल्क में कमी से सरकार के राजस्व पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा एटीएफ पर बढ़ाए गए शुल्क का प्रभाव विमानन कंपनियों की लागत पर पड़ेगा, जिससे हवाई किराए महंगे हो सकते हैं। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यदि वैश्विक तेल कीमतों में तेजी जारी रहती है, तो भविष्य में सरकार को राजकोषीय संतुलन बनाए रखने के लिए अन्य कदम उठाने पड़ सकते हैं।

UP बन रहा ई-रिक्शा और लाजिस्टिक्स EV का हब

- उद्योग में टिकाऊ विकास की ओर बढ़त

एजेंसी । नई दिल्ली

भारत का इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र अब शुरुआती तेज विस्तार के दौर से निकलकर स्थिर और दीर्घकालिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में वही कंपनियां बाजार में टिक पाएंगी, जिनके पास मजबूत वित्तीय आधार, उन्नत तकनीक और सुदृढ़ सप्लाई चेन होगी। इसी बीच उत्तर प्रदेश ई-रिक्शा और लॉजिस्टिक्स से जुड़े इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है।

देशभर में 12 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया

उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में देशभर में 11 से 12 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया और 6 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश इस वृद्धि में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जहां ई-रिक्शा और ई-ऑटो की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज को 82000 करोड़ की चपत

एजेंसी । नई दिल्ली

केंद्र सरकार द्वारा डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स दोबारा लागू किए जाने के बाद शेयर बाजार में दबाव देखने को मिला। इस फैसले का सबसे बड़ा असर Reliance Industries Limited (RIL) के शेयरों पर पड़ा, जो शुक्रवार को 4 प्रतिशत से अधिक टूट गए। इसके चलते कंपनी के बाजार पूंजीकरण में करीब 82,000 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई। सरकार की ओर से इस कदम को घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

पश्चिम एशिया तनाव से सहमा बाजार

- निवेशकों को 8.89 लाख करोड़ रुपये का लगा फटका
- सेंसेक्स-निफ्टी में तेज गिरावट, लाल निशान में हुए बंद

एजेंसी । नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। दिनभर बिकवाली के दबाव में रहे प्रमुख सूचकांक BSE Sensex और Nifty 50 क्रमशः 2.25 प्रतिशत और 2.09 प्रतिशत लुढ़क गए। निवेशकों की सतर्कता और अनिश्चित माहौल के चलते बाजार में पूरे सत्र के दौरान नकारात्मक रुख बना रहा।

मार्केट कैप में नौ लाख करोड़ की कमी

आज शेयर बाजार में आई कमजोरी के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में करीब नौ लाख करोड़ रुपये की कमी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद घट कर 422.12 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया। जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 431.01 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 8.89 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। कारोबार के दौरान लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए।

मिड, स्माल कैप में भारी बिकवाली

गिरावट का असर केवल बड़े शेयरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी तेज बिकवाली देखी गई। व्यापक गिरावट के चलते निवेशकों की संपत्ति में करीब 9 लाख करोड़ रुपये की कमी आंकी गई। बाजार पूंजीकरण में आई इस गिरावट ने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी है। दिनभर के कारोबार में गिरावट का दबाव इतना अधिक रहा कि दोनों प्रमुख सूचकांक अपने निचले स्तर के करीब बंद हुए।

डॉलर की मजबूती से रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया

- वैश्विक तनाव ने बढ़ाया दबाव, 94.29 रुपया प्रति डॉलर

एजेंसी । नई दिल्ली

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में शुक्रवार को तेज गिरावट दर्ज की गई और शुरुआती कारोबार में यह 33 पैसे टूटकर 94.29 प्रति डॉलर के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 93.96 पर बंद हुआ था। विदेशी मुद्रा बाजार में यह गिरावट निवेशकों की सतर्कता और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आई है। विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम एशिया में जारी तनाव और संभावित लंबे संघर्ष की आशंका ने रुपये पर दबाव बढ़ाया है।

लंबे संघर्ष की आशंका में रुपये पर दबाव

विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम एशिया में जारी तनाव और संभावित लंबे संघर्ष की आशंका ने रुपये पर दबाव बढ़ाया है। बीते एक महीने में घरेलू मुद्रा करीब 3.5 प्रतिशत कमजोर हो चुकी है। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई हैं, जिससे ऊर्जा आयात पर निर्भर भारत जैसे देशों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। रुपये की कमजोरी का सीधा असर महंगाई पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है।

लोन की ईएमआई पर पड़ेगा असर

इस बीच, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे लोन की ईएमआई पर असर पड़ सकता है। हालांकि, निर्यात आधारित क्षेत्रों जैसे आईटी और फार्मा कंपनियों को कमजोर रुपये से कुछ लाभ मिलने की उम्मीद है। वैश्विक निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से पूंजी निकासी भी रुपये पर दबाव का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। युद्ध की खबरों के बीच भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। विदेशी निवेशकों (FIIs) की बिकवाली के वजह से निफ्टी और सेंसेक्स में दबाव बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहीं, तो कंपनियों की इनपुट लागत बढ़ेगी, जिससे उनके मुनाफे और शेयर की कीमतों पर बुरा असर पड़ेगा।

महंगाई पर पड़ेगा कमजोरी का असर

डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया अपने निचले स्तरों की ओर फिसल रहा है। कमजोर रुपया आयात को और महंगा बना देता है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ता है। इसका सबसे ज्यादा असर BPCL और HPCL जैसी तेल विपणन कंपनियों पर दिख रहा है। हालांकि, कूटनीतिक प्रयासों से बाजार को संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सीथ ही जब तक युद्ध की स्थिति पूरी तरह साफ नहीं होती, निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। भारत की इकोनॉमी इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां एक तकनीकी शब्द सीधे आम आदमी की जेब पर असर डाल सकते हैं।

आईपीएल के पहले मैच में भिड़ेंगे आरसीबी और हैदराबाद

बखिया उधेड़ने वाले बैटर्स के साथ मैदान में उतरेंगी दोनों टीमें

पहले मैच में रनों की बारिश होने की उम्मीद

एजेंसी | बेंगलुरु

गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले से आईपीएल 2026 (IPL 2026) का आगाज होगा। शनिवार, 28 मार्च को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोनों टीमें शाम 7:30 बजे टकराएंगी। हालांकि, इस मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। बेरहमी से बल्लेबाजी करने वाले बैटर से सजी दोनों टीमों की नजर पहले ही मैच में रन वर्षा करने पर होगी।

विराट कोहली एक्शन में

SRH के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से फिल सॉल्ट और विराट कोहली पारी का आगाज करते नजर आ सकते हैं। टी20 विश्व कप 2026 में इंग्लैंड के लिए सॉल्ट का हालिया प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ 130 रन बनाए। फिल के अनुभव को देखते हुए उन्हें ओपनिंग मैच के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। जैकब बेथेल की शानदार फॉर्म को नजरअंदाज करना मुश्किल है। देवदत्त पडिक्कल आरसीबी की बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। वह 3 नंबर पर उतर सकते हैं। इस स्थान पर वह विस्फोटक सलामी जोड़ी और मिडिल ऑर्डर के बीच कड़ी का काम करेंगे। हालांकि पडिक्कल आरसीबी के लिए तीसरे नंबर पर पहली पसंद होंगे, लेकिन उन्हें वेंकटेश अय्यर से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2026 की नीलामी में 7 करोड़ रुपये में खरीदा था।

हेड टू हेड

कुल मुकाबले	: 25
आरसीबी ने जीते	: 11
हैदराबाद ने जीते	: 14

पाटीदार की कप्तानी में जीता खिताब

आरसीबी को अपनी कप्तानी में पहला खिताब जिताने वाले रजत पाटीदार 4 नंबर पर नजर आ सकते हैं। फिल जितेश शर्मा विकेटकीपर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड जैसे पावर-हिटर भी अंतिम 11 में जगह बना सकते हैं। हालांकि, शेफर्ड और जैकब बेथेल में से किसी 1 को ही मौका मिल पाएगा। टिम डेविड फिनिशर का रोल प्ले करेंगे। आईपीएल 2025 के फाइनल में अपनी टीम के लिए अहम भूमिका निभाने वाले स्टार ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या आरसीबी को बल्ले और गेंद दोनों से सही संतुलन प्रदान करेंगे। भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की जिम्मेदारी यश दयाल और जोश हेजलवुड की अनुपस्थिति में बढ़ गई है। वहीं जैकब डफी भी नई गेंद से बॉलिंग के एक ऑप्शन हो सकते हैं।

नियमित कप्तान कमिंस अभी ठीक नहीं

मध्य क्रम की बात करें तो चौथे नंबर पर हेनरिक क्लासेन के बने रहने की संभावना है। वहीं लियाम लिविंगस्टोन पांचवें नंबर पर नजर आ सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी भी 11 प्लेयर्स में जगह बना सकते हैं। इसके अलावा अनिकेत वर्मा और ऑलराउंडर हर्ष दुबे नजर आ सकते हैं। कप्तान पैट कमिंस के वापसी करने तक जयदेव उनादकट और हर्षल पटेल तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे। वहीं, जीशान अंसारी स्पिन गेंदबाजी के मुख्य विकल्प के रूप में नजर आएंगे। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच टी20 मैचों के लिए बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। यहां की छोटी बाउंड्री और फ्लैट विकेट बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका देती है। तेज गेंदबाजों को यहां काफी समझदारी से गेंदबाजी करनी होगी, जबकि स्पिनर्स को गेंद को रोककर और टर्न दिलाकर असर दिखाना होगा।

मैच के आंकड़े

RCB vs SRH के मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए हैं. इस खिलाड़ी ने 24 मैचों में 805 रन बनाए हैं.इन दोनों टीमों के बीच मुकाबले में सबसे बड़ी पारी जॉनी बेयरस्टो ने खेली है, जिन्होंने SRH के लिए खेलते हुए 56 गेंदों में 114 रन बनाए थे. इन दोनों के बीच मुकाबले में डेविड वॉर्नर ने सबसे ज्यादा 33 छक्के जड़े हैं.बेंगलुरु की टीम हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 68 रन पर भी ढेर हो चुकी है जो कि सबसे छोटा स्कोर है. हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच पिछले सीजन में एक ही मुकाबला हुआ था जिसमें ईशान किशन ने कहर बरपा दिया था।

मंगेश कर सकते डेब्यू

यश दयाल की गैरमौजूदगी में मध्य प्रदेश के होनहार बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मंगेश यादव के लिए रास्ता खुल गया है। उन्हें शनिवार को डेब्यू का मौका मिल सकता है। फ्रेंचाइजी ने मिनी ऑक्शन में उन पर 5.2 करोड़ रुपये खर्च किए थे। सुयश शर्मा या रसिक डार को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतारा जा सकता है। हैदराबाद के टॉप ऑर्डर की बात करें तो उनके पास विस्फोटक बल्लेबाजों की पूरी फौज है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करते हैं, जबकि ईशान किशन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं। ईशान 2025 से ही बल्ले से तबाही मचा रहे हैं।

गुरजंत सिंह ने लिया संन्यास

एजेंसी | नई दिल्ली

भारतीय पुरुष हॉकी टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ी गुरजंत सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की। 31 साल के स्टार ने भारतीय टीम के लिए 130 मैचों में 33 गोल किए। 26 जनवरी 1995 को अमृतसर के खैलारा में जन्मे गुरजंत के मन में बचपन से ही हॉकी के प्रति लगाव था। इस खेल में बेहतर बनने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। गुरजंत ने 2016 में लखनऊ में फाइनल में गोल करते हुए भारत की जूनियर विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी। 2017 में गुरजंत ने सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया था। गुरजंत की सबसे बड़ी उपलब्धियां ओलंपिक मंच पर सामने आईं, जहां वे टोक्यो 2020 और पेरिस 2024, दोनों ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीमों का एक अहम हिस्सा थे। ओलंपिक के अलावा गुरजंत ने भारत को 2022 हांगझोऊ एशियाई खेलों में स्वर्ण, 2017 एशिया कप में स्वर्ण और कई एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीतने में मदद की। 2021 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारत के सर्वोच्च खेल सम्मानों में से एक है।

हॉकी इंडिया अवॉर्ड्स 2025 का एलान

नवनीत कौर और हार्दिक सिंह बने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

एजेंसी | नई दिल्ली

अनुभवी फॉरवर्ड नवनीत कौर और मिडफील्डर हार्दिक सिंह को आठवें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कारों में वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया। दोनों को हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से नवाजा गया और पुरस्कार स्वरूप 20-20 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया।

जफर इकबाल को मिला लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार

1980 मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने आशा जताई कि भारतीय टीम फिर से ओलंपिक चैंपियन बनेगी।

अन्य प्रमुख पुरस्कार विजेता

वर्ष 2025 के अन्य प्रमुख पुरस्कार विजेताओं में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर (बलजीत सिंह पुरस्कार) के लिए बीचू देवी खरीबम, सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर (परगट सिंह पुरस्कार) के लिए संजय, सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर (अजित पाल सिंह पुरस्कार) के लिए सुमित और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड (धनराज पिल्लई पुरस्कार) के लिए सुखजीत सिंह को सम्मानित किया गया।

न्यूज़ ब्रीफ

हम 31 मई को ट्रॉफी जीतेंगे : शशांक

नई दिल्ली। पिछले साल आईपीएल के फाइनल में चूकने के बाद शशांक सिंह को पूरा भरोसा है कि पंजाब किंग्स इस सत्र में 31 मई को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतेगी। पंजाब एक दशक के लंबे इंतजार के बाद फाइनल में पहुंची थी पर बेंगलुरु से छह रन से हारकर मौका चूक गई थी। शशांक ने शुक्रवार को कहा, मुझे पता है कि 31 मई को हम चिन्नास्वामी में खेलेंगे और कप जीतेंगे। यह सिर्फ एक अहसास नहीं है, बल्कि मुझे यह पक्का पता है कि ऐसा जरूर होगा। उन्होंने कहा, यह खुद पर और टीम पर भरोसा है। हर किसी की एक ही सोच है। हर कोई आत्मविश्वास से भरा है।

गिरोड के सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड बराबर करने के करीब एम्बापे

फॉक्सबोरो। स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे फ्रांस की ओर से सर्वाधिक गोल करने के ओलिवियर गिरोड के रिकॉर्ड की बराबरी से सिर्फ एक गोल दूर रह गए हैं। उन्होंने गुरुवार देर रात को फ्रांस की टीम को ब्राजील के खिलाफ मैत्री फुटबॉल मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनके अलावा ह्यूगो एकितिके ने भी गोल किया जिससे फ्रांस ने ब्राजील को 2-1 से पराजित किया। फ्रांस रविवार को मैरीलैंड के लैंडओवर में कोलंबिया के खिलाफ मैत्री मैच खेलेगा। एमबापे मुकाबले से पहले घुटने की चोट से जूझ रहे थे।

भारतीय कंपाउंड तीरंदाजों का दबदबा जारी

एजेंसी | बैंकॉक

भारतीय कंपाउंड तीरंदाजों ने एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट के पहले चरण में अपना दबदबा जारी रखा है। मिश्रित टीम ने जहां स्वर्ण पदक जीता तो वहीं, महिला टीम रजत पदक हासिल करने में सफल रही। पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में तो भारत ने क्लीन स्वीप कर लिया। इस टूर्नामेंट में भारत ने अब तक दो स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है और उसके कुल पदकों की संख्या आठ हो गई है जो पिछले साल के टूर्नामेंट के बराबर है।

पुरुष कंपाउंड वर्ग में क्लीन स्वीप

दिन का मुख्य आकर्षण पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में क्लीन स्वीप रहा। उदय कंबोज ने रोमांचक फाइनल में हमवतन प्रथमेश जवकर को 145-144 से हराकर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता, जबकि अनुभवी खिलाड़ी रजत चौहान ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत इस स्पर्धा में क्लीन स्वीप करने में सफल रहा।

तेजल ने जीता कांस्य पदक

18 वर्षीय तेजल साल्वे ने तटस्थ ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा कर रही रूसी तीरंदाज मारिया दिमिडियुक को 144-135 से हराकर महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। सुबह के सत्र का मुख्य आकर्षण चिकिता तनिपार्थी और रजत चौहान की शीर्ष वरीयता प्राप्त मिश्रित टीम जोड़ी थी, जिन्होंने स्वर्ण पदक मुकाबले में दूसरी वरीयता प्राप्त मलयेशिया को 158-156 से हराया। चिकिता, राज कौर और तेजल साल्वे की भारतीय महिला कंपाउंड टीम को फाइनल में कजाकिस्तान की विक्टोरिया ल्यां, डायना युनुसोवा और रोक्साना युनुसोवा से 227-229 से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय महिला टीम पिछली बार कांस्य पदक ही जीत पाई थी और इस तरह से उसने अपने प्रदर्शन में सुधार किया। भारत ने मजबूत शुरुआत की और 12 तीरों के बाद आधे चरण में 115-113 की बढ़त बना ली। तीसरे सेट में हालांकि भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और वह 54 अंक ही बना सकी, जबकि कजाकिस्तान की टीम ने 58 अंक बनाए। इस तरह से उसने 171-169 की बढ़त हासिल कर ली।

बॉ ली वु ड

2 अप्रैल बनेगा खास दिन 'रामायण' में 'राम' का भव्य अवतार आएगा सामने

रामायण साल 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल है, जिसे एक भव्य ग्लोबल सिनेमाई स्पेक्टेकल के रूप में तैयार किया जा रहा है। नितेश तिवारी के निर्देशन और नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बन रही यह महाकाव्य फिल्म दो भागों में रिलीज होगी। फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिएटिव टैलेंट के साथ तैयार किया जा रहा है, जिससे इसे एक ऐतिहासिक सिनेमाई इवेंट माना जा रहा है। राम नवमी के शुभ अवसर पर नमित मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट शेयर करते हुए फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि 'रामायण' केवल एक कहानी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी धरोहर है, जिसे पूरी जिम्मेदारी और श्रद्धा के साथ जीवंत किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि 2 अप्रैल, हनुमान जयंती के दिन फिल्म से 'राम' की अगली झलक का भव्य

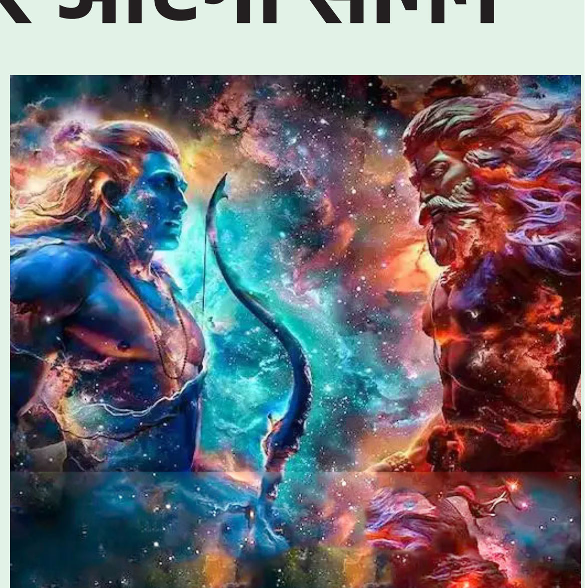

वर्ल्ड रिवील किया जाएगा। करीब 5,000 साल पुरानी पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित रामायण को आधुनिक तकनीक और इमर्सिव स्टोरीटेलिंग के साथ पेश किया जा रहा है। फिल्म का पहला लुक पहले ही दुनियाभर में चर्चा बटोर चुका है, जिसमें भारत के कई शहरों के साथ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी इसकी झलक दिखाई गई थी। मेकर्स इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक वैश्विक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में पेश करने की तैयारी में हैं। फिल्म की स्टारकास्ट भी इसे खास बनाती है। रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे। यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के सहयोग से बन रही यह फिल्म आईमैक्स पर रिलीज होगी, जिसका पहला भाग दिवाली 2026 और दूसरा भाग दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में आएगा।

सलमान खान की फिल्म से जुड़े अनिल कपूर

सलमान खान निर्माता दिल राजू और निर्देशक वामशी पेडिपल्ली की फिल्म को लेकर खूब सुर्खियां बटो रहे हैं। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह उच्च स्तर की एक्शन-थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें अभिनेता के साथ, नयनतारा की जोड़ी बनेगी। फिल्म का शीर्षक तया होना बाकी है। इन खबरों ने पहले से फैंस का उत्साह बढ़ाकर रखा है और अब एक नया अपडेट सामने आ गया है। बताया जाता है कि अभिनेता अनिल कपूर भी इस आगामी परियोजना का हिस्सा बन रहे हैं। बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड के मुताबिक, दिल राजू और पेडिपल्ली की आगामी फिल्म में पहले से 2 दमदार सितारे सलमान और नयनतारा मुख्य भूमिकाओं में हैं। अब इस परियोजना में अनिल की मौजूदगी भी शामिल हो गई है। वैसे तो निर्माताओं की ओर से अब तक किसी भी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सलमान की फिल्म में अगर वाकई अनिल शामिल होते हैं, तो यह फैंस के लिए दोहरे जश्न का मौका होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, परियोजना से जुड़े अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि फिल्म की शूटिंग अप्रैल, 2026 से शुरू करने की योजना बनाई गई

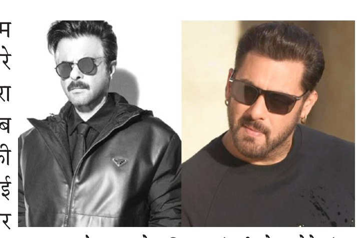

है। इसके लिए मुंबई के गोरेगांव स्थित SRPF ग्राउंड में एक भव्य सेट का निर्माण भी किया गया है। सूत्र ने यह भी बताया कि निर्माता फिल्म को 2027 तक बड़े पर्दे पर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। फिलहाल, सलमान की चर्चित परियोजना में 'मातृभूमि' शामिल है जो अगस्त, 2026 में रिलीज हो सकती है।

राम चरण बने 'पेड्डी पहलवान'

'पेड्डी' साल 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में अपनी जगह लगातार मजबूत कर रही है। फिल्म के हर नए कंटेंट के साथ दर्शकों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। अनाउंसमेंट वीडियो में जहां राम चरण को एक गांव के क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में दिखाया गया था, वहीं अब 'पेड्डी पहलवान' कंटेंट में उनका शानदार ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, जिसमें वह कुश्ती के मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। यह बदलाव इंडस्ट्री के बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन्स में गिना जा रहा है। फिल्म के नए विजुअल्स में राम चरण का टोंड फिजीक और पहलवान

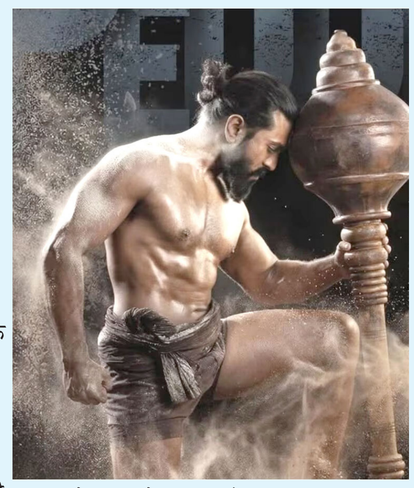

के रूप में उनकी तैयारी साफ झलकती है। क्रिकेट से कुश्ती की ओर उनका यह ट्रांजिशन न सिर्फ यूनिक है, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक खेल कुश्ती को भी बेहद प्रामाणिक तरीके से पेश करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाई ट्रीटमेंट इस बदलाव को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। इससे पहले रिलीज हुए गाने 'चिकिरी चिकिरी' और 'राय राय रा रा' भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके हैं, जिससे फिल्म का हाइप लगातार बढ़ रहा है। बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर, जगपति बाबू, शिवा राजकुमार और दिव्येंदु शर्मा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ए. आर. रहमान के संगीत से सजी यह फिल्म 30 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसे लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है।

मलाइका अरोड़ा ने रिश्तों पर की खुलकर बात

बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में मॉडल सोराब बेदी के साथ उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद दोनों के अफेयर की चर्चाएं तेज हो गई थीं। अब इन अफवाहों पर मलाइका ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है और इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। हालिया बातचीत में मलाइका ने कहा कि हर बार किसी के साथ दिखने पर उनका नाम जोड़ना अब बेहद अजीब और परेशान करने वाला हो गया है। उन्होंने साफ किया कि सोराब बेदी उनके अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है, जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा है। मलाइका ने बताया कि वह इन अफवाहों को अब गंभीरता से नहीं लेतीं। उन्होंने कहा कि वह और उनके बेटे अरहान खान इन खबरों पर साथ बैठकर हंसते हैं। उनके मुताबिक, हम दोनों इन खबरों पर खूब ठहाके लगाते हैं। अभिनेत्री ने अपने रिश्तों को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी साथी की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ होना एक खूबसूरत एहसास है। मलाइका ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रही हैं और किसी रिश्ते की तलाश में नहीं हैं। गौरतलब है कि मलाइका अरोड़ा ने अभिनेता अरबाज खान से 1998 में शादी की थी। दोनों का एक बेटा अरहान है। हालांकि, 2017 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद मलाइका का नाम अभिनेता अर्जुन कपूर के साथ जुड़ा, लेकिन कुछ समय पहले दोनों के अलग होने की खबरें भी सामने आईं। मलाइका ने अपने बयान में यह भी साफ कर दिया कि अगर वह भविष्य में किसी रिश्ते में आती हैं, तो वह फैसला पूरी तरह उनकी शर्तों पर होगा। फिलहाल, अभिनेत्री अपनी जिंदगी के इस दौर को पूरी तरह एंजॉय कर रही हैं।

वॉर ब्रीफ

ईरान को दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने की इजाजत नहीं : ब्रिटेन

वॉक्स-डे-सेर्नी। ब्रिटेन की विदेश सचिव यवेट कूपर ने मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के जल्द समाधान और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की अपील की है। पेरिस के बाहरी इलाके में जी7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में बोलते हुए, कूपर ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते को रोककर वैश्विक अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है। यह जलडमरूमध्य तेल की ढुलाई के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है।उन्होंने कहा,ईरान को इस जलडमरूमध्य के जरिए दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

अतिरिक्त 10 हजार सैनिकों की तैनाती करेगा अमेरिका

वाशिंगटन। इस्राइली मीडिया यरूशलम पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में अतिरिक्त 10 हजार सैनिकों की तैनाती करने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, इस तैनाती में 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के अलावा पैदल सेना और बख्तरबंद वाहनों को शामिल किया जा सकता है। एयरबोर्न डिवीजन की तैनाती को ईरान के खर्ग द्वीप पर हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ये साफ नहीं है कि अन्य सैनिकों की कहां तैनाती की जाएगी। यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है, जब अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की डेडलाइन 6 अप्रैल तक टाल दी है।

जर्मनी ने रूस पर ईरान की मदद का आरोप लगाया

बर्लिन। जर्मनी ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह ईरान को हमले के टारगेट पहचानने में मदद कर रहा है। फ्रांस में G7 बैठक के दौरान जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध से ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस ईरान को संभावित हमलों के टारगेट की जानकारी दे रहा है। इससे दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग साफ दिखता है। जर्मनी के मुताबिक, मिडिल ईस्ट और यूक्रेन के संघर्ष आपस में जुड़े हुए हैं और इन्हें अलग-अलग नहीं देखा जा सकता।

हूती विद्रोहियों ने ईरान के लिए जंग में उतरने की चेतावनी दी

यमन। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले बढ़ाए, तो वे जंग में उतर सकते हैं। हूती प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि यमन ईरान के समर्थन में जंग में शामिल हो सकता है। अधिकारी ने इसे धार्मिक, नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी बताया। हूतियों ने कहा कि अगर हालात और बिगड़े, तो वे पहले ही हस्तक्षेप कर सकते हैं और बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट को बंद करना भी एक विकल्प है। यह स्ट्रेट ग्लोबल शिपिंग के लिए बेहद अहम है और इसके बंद होने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि, अभी तक हूती नेतृत्व ने औपचारिक रूप से जंग में शामिल होने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनकी चेतावनी से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।

इजरायल ने ईरान के मिसाइल निर्माण ठिकानों पर बरसाए बम

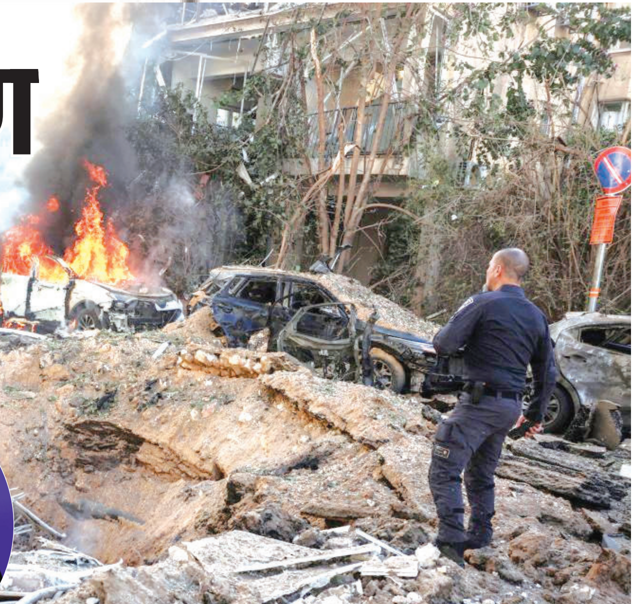

एजेंसी । दुबई/तेहरान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध खत्म करने पर बातचीत के दावों के बीच इजरायल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले शुक्रवार को भी जारी रखे। इजरायली सेना ने ईरान के मिसाइल और हथियार बनाने के ठिकानों पर बम बरसाए, वहीं ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों पर मिसाइल तथा ड्रोन से हमला किया। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान के शहर कोम पर इजरायली हमले में 18 लोगों की मौत हो गई।आईआरजीसी-समर्थित फार्स न्यूज एजेंसी और तस्नीम ने बताया कि यह हमला शुक्रवार की सुबह शहर के परदीसन इलाके में हुआ। हमले में 10 लोग घायल भी हुए हैं।

तेहरान के मध्य पर हमला

इजरायली सेनाइजरायल की सेना ने बताया कि तेहरान के मध्य में स्थित उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जिनका इस्तेमाल ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें और अन्य हथियार बनाने के लिए करता है। सेना ने यह भी बताया कि उसने पश्चिमी ईरान में मिसाइल लॉन्चरों और भंडारण स्थलों पर भी हमला किया गया।लेबनान की राजधानी बेरूत पर भी बम बरसाए गए हैं। वहीं इजरायल में हवाई हमले के सायरन सुनाई दिए, सेना ने कहा कि वह ईरान की मिसाइलों को रोकने का काम कर रही है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा कि ईरान पर हमले और बढ़ेंगे। इन हमलों का दायरा भी बढ़ेगा। काट्ज ने कहा कि उन्होंने और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी आतंकवादी शासन को इजरायल की आम जनता पर मिसाइलें दागना बंद करने की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बावजूद, गोलाबारी जारी है। इसलिए ईरान में हमले बढ़ेंगे और उन अतिरिक्त ठिकानों और इलाकों तक फैलेंगे जो इस शासन को इजरायली नागरिकों के खिलाफ हथियार बनाने और चलाने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा, इस युद्ध अपराध के लिए उन्हें भारी और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।

हमले और बढ़ेंगे: इजरायली रक्षा मंत्री

ईरान ने भी इजरायल, खाड़ी देशों पर दागी मिसाइलें; ड्रोन, कुवैत में बंदरगाह तबाह

ईरान ने इजरायल, कतर, यूएई पर दागी मिसाइलें

ईरान ने इजरायल, कतर, यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। ईरान के हमलों के बाद इजरायल में बम शेल्टर की ओर भागने की अफरा-तफरी में चार लोग घायल हुए हैं। एंबुलेंस सेवाओं के अनुसार ईरानी मिसाइल हमलों के बाद जब निवासी शेल्टर की ओर भागे, तो भगदड़ मच गई इसमें लोग घायल हुए हैं। वहीं, ईरान ने खाड़ी पड़ोसी देशों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। बहरीन, कतर और यूएई में हमले किए गए। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि राजधानी रियाद को निशाना बनाने वाली मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराया है। कुल 17 ड्रोनों को नष्ट किया गया है।

कुवैत में शुवैख बंदरगाह पर हमला

कुवैत ने कहा कि कुवैत शहर में उसके शुवैख बंदरगाह और उत्तर में मुबारक अल कबीर बंदरगाह दोनों पर हमले किए गए। इन हमलों में बंदगगाह को काफी नुकसान पहुंचा है। इन बंदरगाहों का निर्माण चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत चल रहा है। यह पहला मौका है जब खाड़ी क्षेत्र में चीन से जुड़ी किसी परियोजना पर चल रहे युद्ध के दौरान हमला हुआ है।

मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही

युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान में 1900 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह दावा किया है। इजरायल में अठारह लोगों की मौत हुई है, जबकि लेबनान में तीन इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं। युद्ध में अबतक 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में चार और खाड़ी अरब देशों में 20 लोगों की भी मौत हुई है। अधिकारियों ने बताया कि लेबनान में 1100 से अधिक लोगों की मौत हुई है।

अमेरिका, इजरायल तथा उनके सहयोगियों के लिए बंद है होर्मुज : ईरान

एजेंसी । तेहरान

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स(आईआरजीसी) ने शुक्रवार को कहा कि दुश्मन देशों के बंदरगाहों से आने-जाने वाले पोतों के लिए होर्मुज 'बंद' है। ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका और इजरायल के अलावा इन दोनों देशों के समर्थकों के लिए भी होर्मुज स्ट्रेट बंद है और इस मार्ग से किसी भी आवाजाही पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। ईरान के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है। आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि इजरायली-अमेरिकी दुश्मनों के सहयोगियों और समर्थकों के बंदरगाहों तक और वहां से होने वाली शिपिंग किसी भी गंतव्य के लिए प्रतिबंधित है।

तीन पोतों को वापस भेजा

आईआरजीसी ने दावा किया कि उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे तीन पोतों को वापस भेज दिया। गार्ड्स ने अपनी 'सेपाह न्यूज' वेबसाइट पर कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के इस झूठे दावे के बाद कि होर्मुज जलडमरूमध्य खुला है, अलग-अलग देशों के तीन कंटेनर पोतों को आईआरजीसी नौसेना की चेतावनी के बाद वापस भेज दिया गया।

जंग के बीच ईरान ने बच्चों के कंधे पर लादी बंदूक

एजेंसी । तेहरान

अमेरिका- इजरायल से जंग में ईरान ने बच्चों को मोहरा बना मैदान में उतार दिया है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के अधिकारी ने ये जानकारी खुद दी है। अधिकारी ने बताया कि तेहरान की सड़कों पर 12 साल और इससे अधिक उम्र के बच्चे तेहरान की सड़कों पर कंधे पर बंदूक लाद देश की रक्षा में जुटे हैं। इनके पास सुरक्षा से जुड़ी जानकारी जुटाने, निगरानी करने और सेना के लिए वाहनों की व्यवस्था करने का काम है। हथियार से लदे आईआरजीसी के सैन्य ट्रक पर सवार हथियारबंद बच्चे पूरी मुस्तैदी के साथ सड़क से गुजर रही हर कार की सघन तलाशी ले रहे हैं। कावेह के एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि बच्चे जिस कार को रोक रहे हैं वे उसकी पूरी तलाशी लेते हैं। कुछ भी संदिग्ध होने पर अपने वरिष्ठों को सूचना देते हैं। जंग के बीच बच्चे तेहरान में आईआरजीसी के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। ईरानी अधिकारियों ने बताया कि जंग के बीच सुरक्षाबलों का हिस्सा बनने के लिए उम्र को घटाकर 12 साल कर दिया गया है।

लोगों को सतर्क कर रहे हैं

मिसाइल हमले की स्थिति में सेना के साथ काम कर रहे ये बच्चे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए अपील करते हैं। बच्चे लोगों को लगातार इस बात के लिए भी आगाह कर रहे हैं कि जरूरत नहीं हो तो घर के अंदर रहिए। सड़कों पर खतरा है। बच्चे घायलों तक मदद पहुंचाने का भी काम कर रहे।

रात में सड़कों पर नारेबाजी

तेहरान के एक स्थानीय निवासी ने बताया कि सेना के लिए काम कर रहे ये बच्चे रात के समय स्थानीय लोगों की कार और आईआरजीसी का झंडा लेकर सड़कों पर निकलते हैं। स्पीकर की मदद से तेज आवाज में नारेबाजी करते हैं और बताते हैं कि हम दुश्मनों को कड़ा जवाब दे रहे हैं।

दुश्मन से लड़ना चाहते हैं बच्चे

आईआरजीसी का कहना है कि जंग के हालात के बीच बड़ी संख्या में बच्चों ने देश और सेना के लिए काम करने की इच्छा जताई थी। इसी के बाद ये फैसला किया गया। सेना का कहना है कि बच्चे देश के भीतर अपनी जिम्मेदारी बेहतर ढंग से निभा रहे हैं। दुश्मनों से हमारी लड़ाई पूरी मजबूती से जारी है।

लोकसभा में पेश हुआ जन विश्वास विधेयक

- 717 प्रावधानों से हटेगा अपराध का ठप्पा; अब छोटी गलती पर जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना
- कांग्रेस सांसदों ने किया विरोध, भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका जताते हुए चयन समिति को भेजने की मांग उठाई

एजेंसी । नई दिल्ली

सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया। इसका मकसद छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और नियमों आसान बनाना है। इससे कारोबार करना आसान हो सकेगा। विधेयक को वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पेश किया। इसमें चयन समिति की सिफारिशों को शामिल किया गया है। इस विधेयक का मकसद कुछ कानूनों में बदलाव करने के छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाना और नियमों को सरल बनाना है, ताकि भरोसे पर आधारित शासन को बढ़ावा मिले और लोगों का जीवन और कारोबार करना आसान हो सके।

कांग्रेस सांसदों ने किया विधेयक का विरोध

कांग्रेस सांसद कडियम काव्या और जीके पदवी ने इस विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है। पदवी ने सरकार से अपील की कि इस विधेयक को फिर से चयन समिति या किसी संसदीय समिति के पास भेजा जाए। उन्होंने कहा, यह एक प्रशासनिक चूक है। विधेयक मनमाना है और इससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। इसलिए इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि चयन समिति की रिपोर्ट में असहमति दर्ज करने का विकल्प दिया गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ने क्या कहा?

जितिन प्रसाद ने कहा, इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें केवल छोटे अपराधों को ही अपराध की श्रेणी से हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा, यह विधेयक छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करेगा। साथ ही जुर्माना और सजा को अपराध की गंभीरता के हिसाब से तय किया जाएगा और अपील करने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। इससे लोगों के लिए जीवन जीना और कारोबार करना आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया, इस विधेयक के तहत 23 मंत्रालयों की ओर से लागू 79 केंद्रीय कानूनों के कुल 784 प्रावधानों में बदलाव प्रस्तावित है। इनमें 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव है, ताकि कारोबार करना आसान हो सके, जबकि 67 प्रावधान लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए बदले जाएंगे।

मार्च 2025 में पीयूष गोयल ने पेश किया था विधेयक

इस विधेयक को 17 मार्च को चयन समिति की सिफारिशों को शामिल करने के लिए लोकसभा से वापस ले लिया गया था, ताकि इसे फिर से पेश किया जा सके। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 18 मार्च 2025 को यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, जिसके बाद इसे चयन समिति को भेज दिया गया था। यह प्रक्रिया 2023 के जन विश्वास कानून की सफलता पर आधारित है, जिसमें कई कानूनों में छोटे अपराधों को खत्म किया गया था। 11 अगस्त 2023 को लागू इस कानून के तहत 19 मंत्रालयों के 42 केंद्रीय कानूनों में 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया था।

भारत की सैन्य ताकत में होगा इजाफा

एजेंसी । नई दिल्ली

- 2.38 लाख करोड़ के रक्षा सौदों पर मुहर
- S-400 की अतिरिक्त खरीद को मंजूरी

भारतीय सेना और वायुसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने शुक्रवार को एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। लगभग 2.38 लाख करोड़ रुपये के सैन्य साजो-सामान की खरीद को मंजूरी दी गई है। यह निवेश न केवल सीमाओं की सुरक्षा को पुख्ता करेगा, बल्कि भारतीय सेनाओं को आधुनिक तकनीक से भी लैस करेगा। थल सेना की ताकत बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रणालियों को मंजूरी मिली है। 'एयर डिफेंस ट्रैक्ड सिस्टम' रीयल-टाइम में हवाई खतरों की निगरानी और रिपोर्टिंग करेगा। वहीं, 'उच्च क्षमता वाला रेडियो रिले' युद्ध के मैदान में बिना किसी गलती के भरोसेमंद संचार सुनिश्चित करेगा, जो जीत के लिए बेहद ज़रूरी है।

तोपखाने की धाक और सटीक निशाना

धनुष गन सिस्टम' के आने से भारतीय तोपखाने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। यह लंबी दूरी के लक्ष्यों को बेहद सटीकता के साथ निशाना बनाने में सक्षम है। साथ ही, 'आर्मर्ड पियर्सिंग टैंक एम्यूनिशन' दुश्मन के मजबूत से मजबूत टैंकों को भी तबाह करने की ताकत देगा। सेना की नजरें अब और तेज होंगी। 'रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस सिस्टम' के जरिए सैन्य इकाइयां बिना किसी रनवे की जरूरत के, दुर्गम इलाकों में भी दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकेंगी।

वायुसेना के पंखों को मिलेगी नई उड़ान

भारतीय वायुसेना के लिए मध्यम परिवहन विमान और लंबी दूरी की घातक सतह-से-वायु मिसाइल प्रणाली S-400 के प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। इसके अलावा, दूर से नियंत्रित हमलावर विमान यानी 'कॉम्बैट ड्रोन्स' भी वायुसेना के बेड़े का हिस्सा बनेंगे, जिससे बिना पायलट के जोखिम के दुश्मन पर हमला किया जा सकेगा। वायुसेना के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान सुखोई-30 के एयरो इंजन के कलपुर्जों की मरम्मत और 'ओवरहाल' को भी मंजूरी दी गई है।

न्यायिक रिक्तियों में देरी बर्दाश्त नहीं: सीजेआई

एजेंसी । नई दिल्ली

देश की न्याय व्यवस्था में तेजी लाने की दिशा में मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। CJI ने देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जजों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पत्र की सबसे खास बात महिला जजों की नियुक्ति को लेकर सीजेआई का सख्त रुख है। सीजेआई सूर्यकांत ने अपने पत्र में जिक्र किया है कि उच्च न्यायपालिका में

महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भी काफी कम है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट कॉलेजियम को महिला जजों की नियुक्ति को अपवाद के तौर पर नहीं, बल्कि सामान्य नियम के रूप में देखना चाहिए। मेधावी महिला वकीलों को बेंच का हिस्सा बनाना केवल संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता लाने के लिए अनिवार्य है।

तीन विधेयकों पर जेपीसी की रिपोर्ट के लिए बढ़ी समय सीमा

नई दिल्ली। लोकसभा ने शुक्रवार को तीन अहम संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा बढ़ा दी। अब यह रिपोर्ट 2026 के मानसूत्र सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन तक पेश की जाएगी। इन विधेयकों में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025; जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार, 2025 शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद अपराजिता सारंगी ने सदन में इस समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इन प्रस्तावित संशोधनों में यह प्रावधान भी किया गया है।

तृणमूल के खिलाफ भाजपा का 'आरोपपत्र' जारी करेंगे अमित शाह

- ममता बनर्जी सरकार को घेरने के लिए भाजपा ने तैयार किया है आरोपों का संकलन

एजेंसी । कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के खिलाफ भाजपा का 'आरोपपत्र' जारी करेंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, इस दस्तावेज के जरिए ममता बनर्जी सरकार के 15 साल के कार्यकाल की कथित विफलताओं को जनता के सामने रखा जाएगा।

14 मुद्दों पर टीएमसी को घेरने की तैयारी

भाजपा ने अपने 'अभियोगनामा' में भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित कुल 14 प्रमुख मुद्दों को शामिल किया है। पार्टी का दावा है कि इन सभी बिंदुओं पर टीएमसी सरकार विफल रही है और इन्हीं मुद्दों को चुनावी अभियान का केंद्र बनाया जाएगा।

संकल्प पत्र में पेश होंगे समाधान

वरिष्ठ नेता ने बताया कि आरोपपत्र जारी करने के बाद भाजपा अपने 'संकल्प पत्र' में इन समस्याओं के समाधान भी पेश करेगी। अमित शाह हाल के महीनों में कई बार पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके हैं और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। राज्य की 294 विधानसभा सीटों के लिए 23 और 29 अप्रैल को मतदान प्रस्तावित है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भाजपा-कांग्रेस विधायकों में हाथापाई

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत को लेकर प्रदर्शन हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता खामेनेई की तस्वीर लेकर सदन के अंदर पहुंचे और

समर्थन में नारेबाजी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओ ने खामेनेई के पोस्टर भी लहराए। इस बीच, सदन में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच धक्का-मुक्की का भी वीडियो सामने आया। हालांकि, ये विवाद भाजपा नेताओं के राहुल पर कमेंट को लेकर था। कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। जवाब में भाजपा विधायक युद्धवीर सेठी ने कहा, 'राहुल गांधी पप्पू हैं।' इसके बाद दोनों नेताओं में हाथापाई होने लगी। वहीं, ईरान युद्ध पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा- ईरान पर यह युद्ध थोपा गया।